प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना कि उसे सही ढंग से खर्च करना। -चार्ल्स एच. स्पर्जन

सीडीएस का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का 15 फीसदी वक्त फर्जी खबरों का मुकाबला करने में बर्बाद हुआ, दर्शाता है कि अब युद्ध केवल सैन्य तैयारी से ही नहीं लड़े जा रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धारणा की लड़ाई के अलावा जब भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ आती है, तब उन्हें विफल करने की तैयारी भी जरूरी बन जाती है।

युद्ध का नया मोर्चा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का पंद्रह फीसदी समय फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में बर्बाद हुआ, केवल एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोरने वाली सच्चाई है। उनका यह बयान आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को तो दिखाता ही है, इसके साथ यह भी दर्शाता है कि सूचना युद्ध अब सैन्य रणनीति का कितना अभिन्न अंग बन चुका है। इससे यह भी पता चलता है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव की लड़ाई, तो दूसरी ओर मीडिया युद्ध क्यों करना पड़ा। दरअसल, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और त्वरित संचार ने गलत सूचनाओं को फैलाने की गति को अभूतपूर्व बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित झूठी खबरों ने लोगों की धारणा को प्रभावित करने की साजिश रची, जिसका सामना भारत ने तथ्य-आधारित और संयमित संचार की रणनीति से किया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के दुष्प्रचार तंत्र द्वारा फैलाई गई भ्रामक सूचनाओं को ही कई देश काफी समय तक सच मानते रहे। वरना ऐसी नौबत ही क्यों आती कि कोलंबिया को पाकिस्तान के साथ सहानुभूति दर्शाने वाले बयान को वापस लेने के लिए राजी होना पड़ा, जब शशि थरूर के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सच्चाई को सामने रखा। इससे यह भी पता चलता है कि प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्णय कितना जरूरी था और ये दल अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक अपनी बात पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। बात सिर्फ कोलंबिया या चुनिंदा देशों की नहीं है, ऐसे बहुतेरे देश होंगे, जो पाकिस्तान के झूठे बयानों की असलियत से अब भी अंजान होंगे। यह स्थिति हमें एक गंभीर सबक देती है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं के मोर्चे पर भी लड़े जा रहे हैं। चूंकि गलत सूचनाओं का प्रभाव केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं रहता; यह जनता के मनोबल, अंतरराष्ट्रीय धारणा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है, जनरल चौहान ने उचित ही सूचना युद्ध के लिए एक समर्पित शाखा की जरूरत पर बल दिया है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब सूचनाओं की बाढ़ आती है, तो उन्हें विफल करना भी तैयारी की बात बन जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की क्षमता को तो प्रदर्शित किया ही, साथ ही सूचना युद्ध और साइबर खतरों की गंभीर चुनौतियों को भी उजागर किया। जनरल चौहान का बयान दरअसल हमें इस नए युद्ध क्षेत्र में अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के प्रति आगाह करता है।

अब जर्मनी को पछाड़ने की चुनौती

विकास के समान चरणों में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की भारत से तुलना की जाए, तो आज भारत एक अद्वितीय स्थिति में दिखता है। जर्मनी को पीछे छोड़ने के लिए भारत के पास सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मूलभूत चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ

इस साल भारत ने नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिसाब से जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 4,187 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। यह उपलब्धि केवल संख्यात्मक उन्नति भर नहीं है, बल्कि भारत के विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य और एक शीर्ष अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी वाले देश तथा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के स्वाभाविक नेता के रूप में विश्व पटल पर इसके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। हालांकि, भारत के पास अपने विकास की कहानी को समर्थन देने के लिए मजबूत अनुकूल परिस्थितियां हैं, फिर भी आर्थिक विस्तार को बरकरार रखने के लिए उसे कई तरह के सुधारों की जरूरत है।

भारत ने अपनी जीडीपी को बढ़ाने में लंबी छलांग लगाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 में दसवें नंबर पर थी और वर्तमान के बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में, जब वैश्विक व्यापार युद्ध और भू-राजनीतिक जोखिम दुनिया भर में मंदी के कारण बन रहे हैं, तब भी वह दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इतिहास पर नजर डालें, तो भारत की 4,187 अरब डॉलर की मौजूदा जीडीपी विकास के समान चरणों में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर इसे एक अद्वितीय स्थान पर रखती है। वर्ष 1985 में अमेरिका की जीडीपी 4,300 अरब डॉलर थी, जो दर्शाती है कि भारत चार दशक बाद तुलनात्मक आर्थिक स्तर पर पहुंच गया है। चीन से तुलना करें, तो वर्ष 2007 में चीन की जीडीपी करीब 4,300 अरब डॉलर थी, जो बीते अठारह वर्षों में चीन की तीव्र प्रगति को दर्शाती है, जिससे उसकी मौजूदा जीडीपी 18,000 अरब डॉलर पहुंच गई है। वर्ष 1993 में जापान की अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 4,300 अरब डॉलर था, जो इस बात की चेतावनी देता है कि कैसे आर्थिक ठहराव और 1980 के दशक के रियल एस्टेट व शेयर बाजार के बुलबुले के फटने से लगभग चार दशकों तक वहां ठहराव की स्थिति बनी रही। वर्ष 2021 में जर्मनी की जीडीपी लगभग 4,400 अरब डॉलर थी। इसलिए जीडीपी के इस स्तर तक पहुंचने के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका से करीब चालीस वर्ष, चीन से अठारह वर्ष, जापान से 32 वर्ष और जर्मनी से चार वर्ष पीछे है।

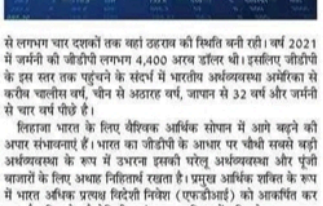

लिहाजा भारत के लिए वैश्विक आर्थिक सोपान में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। भारत का जीडीपी के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना इसकी घरेलू अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजारों के लिए अथाह निहितार्थ रखता है। प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित कर रहा है, जिससे प्रौद्योगिकी, ढांचागत सुविधाओं, फिनटेक, स्वास्थ्य तकनीक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ पूंजी के प्रवाह में बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक विकास की चुनौती से जूझ रहे विश्व में भारत की वृद्धि से फायदा उठाना चाहेंगे। भारत की बेहतर आर्थिक स्थिति से क्रेडिट रेटिंग पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद बंधती है, जिससे उधार लेने की लागत कम होगी और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ने से बाजार पूंजीकरण और अधिक तरलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थितियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार करने होंगे। फिलहाल जी-20 देशों में भारत की श्रम उत्पादकता सबसे कम है। इस समस्या के समाधान के लिए कार्यबल की दक्षता बढ़ाने हेतु कौशल विकास, शिक्षा और तकनीक में निवेश की जरूरत है।

'आत्मनिर्भर भारत' और 'पीएलआई योजना' जैसी पहलों के बावजूद नौकरशाही की बाधाएं और पुराने नियमों जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में सुधार और विनियमन आवश्यक हैं। नीति निर्माताओं को हर चीज का निर्माण करने की कोशिश करने के बजाय रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है, जिनमें भारत तुलनात्मक रूप से बेहतर है। परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे। वित्तीय संस्थानों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने से भी सतत आर्थिक विकास के अनुकूल माहौल बनेगा।

इसके अलावा, तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए भारत को श्रम उत्पादकता बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार करने, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने, कर सुधारों को लागू करने और वित्तीय क्षेत्र को मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इन सुधारों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के साथ भारत एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करा सकता है। जैसे-जैसे भारत इस राह पर आगे बढ़ रहा है, आय और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है, ताकि आर्थिक विकास के लाभों को व्यापक रूप से साझा किया जा सके। समावेशी विकास रणनीतियां दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने और निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

हालांकि, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, फिर भी भारत और जापान के बीच जीवन स्तर, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक अवसंरचना में बहुत बड़ा अंतर है। आईएमएफ के डाटा से पता चलता है कि भारत की वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,880 डॉलर है, जो जापान के 33,960 डॉलर का एक अंश है। जीडीपी का लाभ पूरी आबादी में समान रूप से वितरित करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती है। दूरदर्शी सरकारी नीतियों के साथ-साथ भारत के युवा, शिक्षित और कम लागत वाले कार्यबल के जनसांख्यिकीय लाभ भारत के तुलनात्मक लाभों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आगामी तीन वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी ज्योतिर्मयानंद

एक सुखद विचार आपके तंत्रिका तंत्र में सकारात्मक परिवर्तन, तो अशुभ समाचार तनाव ला देता है। ऐसे में सही चिंतन और शुभ कर्मों से विचारों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित कर सकते हैं।

शरीर पर नाटकीय ढंग से होता है विचारों का प्रभाव

नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले प्राणों से मन का सीधा संबंध है। नाड़ियों की क्रियाशीलता आपके विचारों पर निर्भर करती है। यदि आपके विचार सकारात्मक और उन्नत हैं, तो नाड़ियां खुल जाती हैं और उनसे प्राणों का निर्बाध प्रवाह होने लगता है। यदि आपके विचार विध्वंसात्मक और अशुभ हैं, तो नाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं। कुछ नाड़ियां अधिक तेजी से कार्य करने लगती हैं, जबकि कुछ नाड़ियां मंद अथवा निष्क्रिय हो जाती हैं। इससे आपके मन में तनाव उत्पन्न होता है। जब आपके मन में आनंद और उत्साह का एक विचार उत्पन्न होता है, तो आपका मुखमंडल एक अज्ञात प्रसन्नता और आनंद के कारण चमकने लगता है। इसके विपरीत मन में किसी कुविचार के आते ही आपका चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है। मन व्यक्तित्व का दर्पण बन जाता है।

यदि आप अपने मन में निरंतर नकारात्मक विचार बनाए रखते हैं, तो आपके मुखमंडल की चमक तथा स्वाभाविक सौम्यता समाप्त हो जाती है। पल भर में ही एक सुखद विचार आपके तंत्रिका तंत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला देता है। दूसरे ही पल यदि कोई अशुभ समाचार मिलता है अथवा कोई चिंता आपके मन में हो जाती है, तो तनाव की काली घटा आपको घेर लेती है। प्राणों का प्रवाह सीमित हो जाता है तथा आप दुर्बल हो जाते हैं। शरीर पर विचारों का प्रभाव शीघ्र और नाटकीय ढंग से होता है। फिर भी, आपके व्यक्तित्व और शरीर को स्वस्थ तथा सुंदर बनाने की सकारात्मक सोच की जो शक्ति है, वह दीर्घकालीन अभ्यास पर निर्भर करती है। किसी छात्र ने अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं की है और परीक्षा आते ही वह सकारात्मक विचार करने लगता है। उसने अपने विचारों को सकारात्मक अवश्य बना लिया है, परंतु उसकी क्रियाएं उसके अनुरूप नहीं हुई हैं। इसलिए उसे सफलता नहीं मिलेगी।

यदि आप केवल सकारात्मक चिंतन करके बहुत अच्छे परिणाम की आशा करते हैं, तो आप अपने समस्त तंत्रिका तंत्र को ही दबाव में रख रहे हैं। इसके विपरीत आप सकारात्मक कार्य में संलग्न रहते हुए इस धारणा को पुष्ट करें कि चाहे कितना विलंब क्यों न हो, इसका निश्चित रूप से शुभ परिणाम होगा। उदाहरण के लिए, आप क्रोधी प्रकृति के हैं अथवा बात-बात में झूठ बोलने के आदी हैं, तो आप यह निष्कर्ष न निकालें कि इन बुरी आदतों के विषय में कुछ नहीं कर सकते। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत शिक्षित और विकसित माने जाते हैं, परंतु उनमें आज भी वे सभी ऋणात्मक वृत्तियां विद्यमान हैं, जो उनकी किशोरावस्था में भी थीं। हो सकता है कि उनका सतही रूप भले ही कुछ बदल गया हो। लेकिन सकारात्मक सोच और अच्छे कामों का अभ्यास करने से धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व का नकारात्मक आधार समाप्त होता जाएगा और उसके स्थान पर सकारात्मक स्वरूप प्रतिष्ठित और सुदृढ़ होगा।

मन का निरीक्षण करते रहें

सूत्र

जब आप रचनात्मक चिंतन के अद्भुत प्रभाव का अनुभव करने लगेंगे, तो न केवल आपका शरीर, बल्कि परिस्थितियां भी इस प्रकार परिवर्तित होने लगेंगी, जिससे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। सकारात्मक सोच का अंतिम लक्ष्य भी यही है। आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है।

दूसरा पहलू

कुरुक्षेत्र आने वाले ज्यादातर पर्यटक सबसे पहले महाभारत के युद्धस्थल पर पहुंचकर लाल मिट्टी देखना चाहते हैं।

कुरुक्षेत्र में लाल मिट्टी क्यों तलाश रहे लोग

राजस्थान से आया छात्रों का दल कुरुक्षेत्र बस स्टेशन पर उतरते ही ऑटो चालक से उस स्थान पर ले जाने के लिए कहता है, जहां कौरव-पांडवों के बीच युद्ध हुआ था और उस रक्तपात की वजह से आज भी मिट्टी का रंग लाल है। ऑटो चालक उन्हें छह किलोमीटर दूर तीर्थस्थल ज्योतिसर ले जाकर उतार देता है। पौराणिक मान्यताओं में ज्योतिसर ही वह पवित्र स्थल है, जहां हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यहां वह विशाल वटवृक्ष मौजूद है, जिसे 18 दिन चले महाभारत के युद्ध का साक्षी बताया जाता है। इसी की पावन छाया में श्रीमद्भगवद्गीता का जन्म हुआ।

चंद्रमोहन शर्मा

तीर्थस्थल ज्योतिसर की मिट्टी का रंग लाल न देखकर पर्यटक निराश हो जाते हैं, लेकिन जिज्ञासा भी जागती है कि आखिर इसका रंग लाल क्यों नहीं है।

हालांकि, छात्र यह देखकर निराशा में डूब जाते हैं कि इस रणक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल नहीं है। यह सामान्य मिट्टी की तरह मटमैली है। गाइड जोगा सिंह बताते हैं, 'कुरुक्षेत्र आने वाले ज्यादातर पर्यटक सबसे पहले रक्तरंजित मिट्टी ही देखना चाहते हैं।' सोशल मीडिया की कहानियां सुनकर आने वाले कई लोग, तो सीधे लाल सड़क पर पहुंचते हैं। इसके नाम से आभास होता है कि इसकी मिट्टी का रंग रक्त जैसा होगा, लेकिन यह तारकोल की आम सड़कों की तरह काली है। पहले लाल ईंटों की बनी होने से इसका नाम लाल सड़क पड़ गया। प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा के पांच जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत में फैली 367 तीर्थस्थलों वाली 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में कहीं भी रक्त रंजित लाल भूमि नहीं है? इसका उत्तर केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार के पास है। वह कहते हैं कि पौराणिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, इनका पूरा सम्मान है, लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल रंग की नहीं है। कुरुक्षेत्र नहीं, किसी भी रणक्षेत्र में रक्त की वजह से मिट्टी का रंग लाल नहीं हुआ है। दरअसल, मिट्टी अजैविक है और रक्त जैविक। जीवाणुओं के माध्यम से रक्त कुछ समय में नष्ट हो जाता है। शरीर से निकलने के कुछ समय बाद ही हवा के संपर्क में आकर यह काला पड़ जाता है। हालांकि, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में कुछ जगहों पर लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसके रंग की वजह इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होना है। यूपी और हरियाणा में भी बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। वैसे, कुरुक्षेत्र में पर्यटकों के लिए ब्रह्मसरोवर, बाणगंगा, भीष्म कुंड, कर्ण का टीला, भद्रकाली मंदिर, धरोहर संग्रहालय, कल्पना चावला तारामंडल, शेख चेहली (जिन्हें शेख चिल्ली के नाम से लोग जानते हैं) और गुरुद्वारा छठी पातशाही समेत अनेक दर्शनीय स्थल हैं।

वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार कहते हैं कि कुरुक्षेत्र नहीं, किसी भी रणक्षेत्र में रक्त की वजह से मिट्टी का रंग लाल नहीं हुआ है। दरअसल, मिट्टी अजैविक है और रक्त जैविक। जीवाणुओं के माध्यम से रक्त कुछ समय में नष्ट हो जाता है।

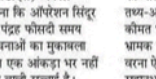

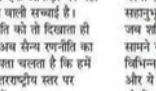

आंकड़े

भोजन पर खर्च

दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जिनके परिवारों का ज्यादातर खर्च भोजन का प्रबंधन करने में ही हो जाता है।

देश	हिस्सेदारी
नाइजीरिया	59.3%
बांग्लादेश	52.8%
यूक्रेन	41.7%
इथोपिया	37.9%
पाकिस्तान	37.8%

आंकड़े घरेलू खर्च में भोजन व्यय की हिस्सेदारी के, भारत में यह 29.9% है। | स्रोत : CIA

एक लकड़हारे ने घायल चिड़िया की देखभाल की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, 'श्याम, तुमने मेरे प्राणी की सेवा की, यह मेरी सच्ची पूजा है।'

जीव की सेवा ही सच्ची पूजा

अंतर्यात्रा
संकलित

एक गांव में श्याम नाम का लकड़हारा रहता था। वह मेहनती था, पर गरीबी के कारण उसके परिवार को दो वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता था। हर सुबह, वह जंगल जाता और मंदिर में भगवान शिव को एक फूल चढ़ाकर काम शुरू करता। उसकी भक्ति सच्ची थी, पर मन में एक सवाल हमेशा रहता, 'क्या भगवान मेरी पुकार सुनते हैं?'

एक दिन, जंगल में उसे एक घायल चिड़िया मिली। उसका पंख टूटा था। वह उड़ नहीं पा रही थी। श्याम ने उसे उठाया, घर लाया और उसकी देखभाल की। उसने सोचा, 'यह ईश्वर की रचना है, इसकी सेवा ही मेरी भक्ति है।' उसने चिड़िया को प्यार से 'मिट्ठू' नाम दिया और रोज उसकी देखभाल की। धीरे-धीरे मिट्ठू ठीक हो गई। एक रात, श्याम ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने कहा, 'श्याम, तुमने मेरे प्राणी की सेवा की, यह मेरी सच्ची पूजा है। जंगल में एक पेड़ के नीचे खजाना है, उसे ले लो।' सुबह श्याम जंगल गया और उस पेड़ के नीचे खोदने पर उसे सोने के सिक्के मिले। उसने उस धन से गांव में एक छोटा-सा आश्रम बनवाया, जहां वह घायल परिंदों की देखभाल करने लगा। श्याम की भक्ति और दया ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि गांव के लोग भी उससे प्रेरित होकर परिंदों और प्रकृति की रक्षा करने लगे। श्याम लोगों से कहता, 'सच्ची भक्ति तो हर जीव की सेवा में है। ईश्वर हमारी पुकार सुनते हैं, हमें विश्वास रखना होगा।'

अमर उजाला

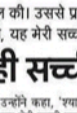

पुराने पन्नों से — 04 जून, 1954

पूर्व बंगाल को पूरी तरह से किया गया नेतृत्व विहीन

पूर्व बंगाल पूरी तरह नेतृत्व विहीन कर दिया गया

पूर्व बंगाल को नए फौजी गवर्नर ने पूरी तरह नेतृत्व विहीन कर दिया है। फजलुलहक घर में ही बंद हैं। सुहरावर्दी कराची में सख्त बीमार हैं, तो मौलाना भषानी लंदन में रुके पड़े हैं। शेष नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है।

थोड़ा है, काफी की जरूरत है

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खासकर गांवों का परिदृश्य बताता है कि अभी काफी कुछ करना बाकी है।

विजय त्रिपाठी | सेहत

यों तो उत्तर प्रदेश में सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल बढ़े हैं। हेल्थ सर्विसेज सेक्टर्स में बड़े-बड़े कॉरपोरेट कदम बढ़ा रहे हैं। आधारभूत ढांचा बदला है, अस्पतालों में संसाधन बढ़े हैं। किडनी और लीवर प्रत्यारोपण शुरू हो गया है। हार्ट और लंग प्रत्यारोपण की तैयारी चल रही है। निजी ही नहीं, सरकारी संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल रहा है? क्या एक्सीडेंट होने पर शुरुआती पहले घंटे यानी गोल्डन आवर में मरीज को उपचार मिल पा रहा है? क्या रात के वक्त प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को उसके घर के आसपास प्रसव की सुविधा मिल पा रही है? आलम यह है कि नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, उसमें 21 प्रदेशों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है।

सरकारी दावों की पोल तब भी खुल जाती है, जब बेहोश मां का स्ट्रेचर खींचते बच्चे की तस्वीर छपती है। जब 29 मई को कानपुर देहात के एक स्वास्थ्य केंद्र पर आधी रात एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बेड के नीचे रखे डस्टबिन में गिरकर उस नवजात की मौत हो जाती है...स्टाफ-डॉक्टर सब सोते रह जाते हैं। सरकारी अस्पताल में जब टॉर्च की रोशनी में सर्जरी होती है। जब झांसी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आग लगने पर 10 बच्चों की मौत हो जाती है। तब पता चलता है कि आईसीयू में 18 की जगह 50 बच्चे भर्ती थे।

इमरजेंसी सेवाओं का हाल यह है कि भाजपा के पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र का बेटा एसजीपीजीआई में तड़प कर मर गया, इमरजेंसी में दाखिला नहीं मिला। पीजीआई भी क्या करे, उस पर दबाव ही इतना है, यूपी-बिहार तो छोड़िए, नेपाल तक का मरीज आ रहा है यहां इलाज पाने। उत्तर प्रदेश के करीब 70 फीसदी से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव बना हुआ है। कैग की हालिया रिपोर्ट ने प्रदेश में डॉक्टरों की 46 फीसदी, तो मेडिकल स्टाफ, नर्स आदि की 38 फीसदी कमी बताई है।

हालांकि, विभाग का दावा है कि उसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिये विभिन्न योजनाओं में इस संख्या से कहीं ज्यादा डॉक्टर तैनात कर रखे हैं। बिडिंग प्रक्रिया के जरिये भी हर साल डॉक्टरों की तैनाती की जाती है। सेवानिवृत्त डॉक्टर को पुनर्नियुक्ति दी जाती है। फिर भी किसी अस्पताल का मुआयना कर लिया जाए, तो हकीकत सामने आ जाती है। अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में सरकार को निजी केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गर्भवती को वाउचर देने पड़ रहे हैं।

पैथोलॉजी जांच के लिए पीपीपी मॉडल का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम कमियों और विसंगतियों के बीच यह सही है कि पिछले पांच-छह वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां भी आई हैं। मस्तिष्क ज्वर में वर्ष 2017 की तुलना में 85.94 फीसदी और मृत्युदर में 99.5 प्रतिशत की कमी आई है। जापानी इंसेफेलाइटिस के रोगियों और मृत्युदर में भारी कमी आई है। कुष्ठ रोग, क्षयरोग, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों में लगातार गिरावट हो रही है।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले-जिले धड़ाधड़ खुल रहे मेडिकल कॉलेजों की चाक-चौबंद व्यवस्था की पोल नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने यह कहकर खोल दी है कि कई कॉलेजों में एमआरआई मशीन लगी है, लेकिन एक भी मरीज की जांच नहीं की गई है। स्टाफ पूरा होने का दावा है, लेकिन उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी का पता नहीं है। हालत यह है कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए बार-बार आवेदन निकाले जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। एमडी-एमएस और डीएम-एमसीएच की डिग्री लेने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर निजी क्षेत्र या दूसरे देश जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रदेश की नीतियों को ही जिम्मेदार माना जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के लिए आयोग से प्रधानाचार्य, सहायक प्रोफेसर चुने जाते हैं, लेकिन वे कार्यभार ग्रहण नहीं करते या उन्हें समय से कार्यभार नहीं दिया जाता है।

तमाम अभियानों के बीच और बावजूद झोलाछापों का धंधा जारी है। ग्रामीण चिकित्सकीय व्यवस्था उन पर इतनी टिकी है कि खुद गांव वाले ही उनकी पकड़-धकड़ के विरोध पर उतारू हो जाते हैं। दलील देते हैं कि कैसे भी हों, दो मारते हैं, तो दस बचाते भी हैं। निजी अस्पताल कुकुरमुत्ते के माफिक बढ़ते जा रहे हैं। उनका विशेषज्ञ चिकित्सकीय सुविधा का दावा नीम-हकीमी ज्यादा है। मरीजों की जान से खेल जाते हैं, तो यदा-कदा ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सांठगांठ से पिछले दरवाजे से चलते रहते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है।

दैनिक जागरण

मौन शांति की पहली सीढ़ी है

राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानक

बांग्लादेश में कट्टरता

बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल हो जाना और उसके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाना भारत के लिए भी चिंताजनक है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, वे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार केवल पाकिस्तान और चीन से ही अपने संबंध बढ़ाने में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि अपने यहां के कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने में भी लगी हुई है। ताजा उदाहरण जमाते इस्लामी का चुनाव लड़ने में सक्षम हो जाना है। यह ठीक है कि इसका पंजीकरण इसलिए बहाल हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के एक सप्ताह के अंदर ही बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ दो अन्य न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया था। इन्हें छात्रों के उसी संगठन ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था जिनके नेतृत्व में शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला था। स्पष्ट है कि अब वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे न्यायाधीश आ चुके हैं जो कार्यवाहक सरकार की हां में हां मिलाने के लिए तैयार हैं। तथ्य यह भी है कि छात्रों के आंदोलन में जमाते इस्लामी ने पूरा सहयोग दिया था। यह वही संगठन है जिस पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान की मदद करने और मानवता के विरुद्ध अपराध एवं नरसंहार के आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते ही उसके छह शीर्ष नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया था।

जमाते इस्लामी कितना कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाला संगठन है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि एक समय जो विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, उसने कुछ समय पहले स्वयं को उससे अलग कर लिया था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर शीघ्र चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक के बाद एक कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाले संगठनों से प्रतिबंध हटने के साथ आतंकी गतिविधियों में जेल की सजा पाए तत्वों को रिहा किया जा रहा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि कट्टरपंथी तत्वों के सिर उठाने से सेना प्रमुख को कोई समस्या नहीं। कहना कठिन है कि सेना प्रमुख के दबाव बनाने के बाद बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि हाल-फिलहाल चुनाव कराने की कोई तत्परता नहीं दिख रही है। भारत को बांग्लादेश की गतिविधियों को लेकर इसलिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वहां पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका का भी प्रभाव बढ़ सकता है।

तस्करों पर कसेगा शिकंजा

पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध जारी है। इस अभियान में काफी संख्या में तस्कर पकड़े जा चुके हैं और उनकी नशा बेचकर बनाई गई संपत्ति पर बुल्डोजर कार्रवाई भी जारी है। अब पंजाब पुलिस नशा तस्करों पर और शिकंजा कसने के लिए जीपीएस ट्रैकर की मदद लेगी। पुलिस बड़े और जमानत पर छूटने वाले नशा तस्करों के पैरों में जीपीएस ट्रैकिंग वाला एंक्लेट डालेगी, जिससे उनकी हर मूवमेंट का पुलिस को पता चलता रहेगा। ऐसा प्रयोग जम्मू-कश्मीर में सफल हो चुका है, जहां जमानत पर रिहा होने वाले आतंकियों के पैरों में इसे डाला गया था। जिस तरह समाज विरोधी तत्व नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस को भी आधुनिक तरीका अपनाने की जरूरत है। नशा तस्करों का हौसला तभी पस्त किया जा सकता है, जब उन पर तकनीक से बड़ा प्रहार हो। डीजीपी ने बताया है कि पुलिस इसे लेकर अध्ययन कर रही है। प्रदेश में नशा तभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है, जब नशा तस्करों की हर चाल की पुलिस के पास काट हो। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान से लगातार नशीले पदार्थों की खेप पहुंचती रहती है। नशा तस्कर फिर अपने संपर्क साधनों की मदद से नशे की खेप की डिलीवरी करते रहते हैं। जीपीएस ट्रैकर से नशा तस्करों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। यदि कोई नशा तस्कर ट्रैकर से छेड़छाड़ भी करेगा तो सूचना तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इससे नशा तस्करों के मंसूबे नाकाम होंगे।

प्रदेश में नशा तस्करों का हौसला तभी पस्त होगा, जब उन पर तकनीक की मदद से बड़ा प्रहार किया जाएगा

तिलक देवाशेर

आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है और अब पाकिस्तान को तय करना है कि वह क्या चाहता है

अवधेश राजपूत

भारत के लिए पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले का संदेश एकदम स्पष्ट था। वह यह कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबक भूल गया है। वह भुला बैठा कि भारत आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलान भी किया था कि आतंकियों और उनके आकाओं के लिए इसके परिणाम उनकी कल्पनाओं से भी परे होंगे। भारत ने पहले गैर-सामरिक मोर्चे पर तत्परता दिखाते हुए तमाम समीकरण बदले। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में त्वरित कदम उठाए गए। इसमें सबसे प्रमुख सिंधु जल समझौते को स्थगित करना था। चूंकि पाकिस्तान सिंचाई संबंधी आवश्यकता के लिए एक बड़ी हद तक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, इसलिए भारत के फैसले से उसे बड़ा झटका लगना स्वाभाविक था। पाकिस्तान की कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

भारत की ऐसी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन भी बाद में उससे मुकर गया। पाकिस्तान ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए तटस्थ जांचकर्ताओं से इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग भी की। पाकिस्तान की ये दलीलें बिल्कुल खोखली थीं। आखिर जिन पर्यटकों के जरिये कश्मीरियों की रोजी-रोटी चलती हो, वे उनको ही क्यों निशाना बनाएंगे। स्पष्ट रूप से यह एक सोची-समझी आतंकी साजिश थी। इसका मकसद सांप्रदायिक तनाव को भड़काना और कश्मीर में फल-फूल रहे पर्यटन को नुकसान पहुंचाना था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अथक प्रयासों से आ रही शांति एवं समृद्धि के दम पर हालात सामान्य होते जा रहे थे। उसे आतंकी छिन्न-भिन्न करना चाहते थे।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की स्वीकारोक्ति ही उनकी मंशा बताने के लिए काफी है। डार ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव के मसौदे के तेवर ढीले कराने के प्रयास किए। इस मूल प्रस्ताव में हमले की जिम्मेदारी लेने वाले रेजिस्टेंस फोर्स की लानत-मलानत की गई थी। उसे स्थानीय लोगों का 'फोरम' बताते हुए पाकिस्तान ने उसे आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने का विरोध किया। अगर यह यह वास्तव में कोई भारतीय फोरम है जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कोई लेनादेना नहीं तो फिर पाकिस्तान ने इस हद तक जाकर उसका संदर्भ क्यों हटवाया? पाकिस्तान इसका जवाब देने में सक्षम नहीं। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तानी मंत्रियों के बयान यही रेखांकित करते रहे कि कैसे इस देश में दशकों से आतंकी ढांचा फलता-फूलता रहा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 25 मई को स्काई न्यूज पर साक्षात्कार में आतंकी ढांचे से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, 'हम तीन दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह गंदा काम (आतंक को पालना-पोसना) करते आए हैं।' पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आतंकी ढांचे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक अतीत रहा है। आतंक पाकिस्तान का अतीत ही नहीं, बल्कि वर्तमान भी है। यह उसकी नीति है।

भारत यह भलीभांति समझने लगा है। पहलगाम की प्रतिक्रिया में गैर-सामरिक मोर्चे पर कदम उठाने के बाद भारत ने सात मई को आपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहावलपुर स्थित जैश और मुरीदके स्थित लश्कर के मुख्यालय भी शामिल थे। ये दोनों जगहें पाकिस्तानी पंजाब में हैं। अपनी कार्रवाई में भारत ने नागरिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन आतंकी ढांचे पर सटीक एवं प्रभावी प्रहार किया। अपनी विश्वसनीयता के लिए भारत ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कि यह कोई खुफिया अभियान न होकर एकदम खुली चेतावनी थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य एवं नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उसे लगा कि भारत परमाणु घुड़की के फेर में आ जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसी कोई परवाह नहीं की। भारत की जवाबी कार्रवाई ऐसी रही जो पाकिस्तान को भुलाए नहीं भूलेगी। उस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। लाहौर और सियालकोट के एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिए गए। 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। इनमें रावलपिंडी स्थित सामरिक महत्व वाला नूर खान बेस, सरगोधा में मुशाफ बेस और जैकबाबाद में शाहबाज बेस प्रमुख हैं। पाकिस्तान यहां अपनी शान मानने वाला एफ-16 विमानों का बेड़ा और परमाणु जखीरा तैनात किए हुए है। भारी दबाव के चलते पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से संपर्क कर शांति की गुहार लगाई।
एक तरह का आत्मसमर्पण ही था। सै
संचालन महानिदेशक स्तर पर हुई बा
के बाद हमले रोकने पर सहमति बनी।

कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ज
भारत विजयी स्थिति में आगे बढ़ रहा
तब उसने शांति की पहल क्यों स्वीक
की? इसका जवाब एकदम सरल है।
भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कि
भारत ने आतंकी ढांचे को ध्वस्त क
दिया और जब पाकिस्तान ने नागरि
को निशाना बनाया तब भी भारत
प्रतिक्रिया संयमित एवं उचित दा
में रही। पाकिस्तानी दुष्प्रचार की पो
खोलने के लिए खुद प्रधानमंत्री आदम
एयरबेस गए। वह जिस सी-130जे सु
हरक्युलिस से उतरे वही पाकिस्तान
दावों को झुठलाने के लिए बहुत था। उस
बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमं
मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आपरेश
सिंदूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ए
न्यू-नर्मल सिद्धांत को स्थापित क
का काम किया। अब कोई भी आतं
हमला युद्ध की चुनौती के रूप में लि
जाएगा और उसकी कड़ी प्रतिक्रिया होग
भारत किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग
शिकार नहीं होगा। आतंकियों और उन
समर्थकों में कोई भेद नहीं किया जाएग
उन्होंने दोटूक कहा कि अगर पाकिस्त
शांति चाहता है तो पहले उसे अपने य
आतंकी ढांचा समाप्त करना होगा। आत
के साथ न वार्ता हो सकती है और
व्यापार। पानी और खून भी एक साथ न
बह सकते। भारत का रुख एकदम स्प
है और अब पाकिस्तान को तय करना
कि वह क्या चाहता है।

(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहक
बोर्ड के सदस्य रहे ह
response@jagran.co

बाहरी विशेषज्ञों की उपयोगिता का प्रश्न

दिनेश वैद्य

दुर्गाशंकर मिश्र

परामर्शदाताओं की विशेषज्ञता सरकारी तंत्र को विकसित करने की होनी चाहिए, न कि स्वयं तंत्र का रूप लेने की

आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए नीति संबंधी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ऐसे में इस पर विचार हो कि क्या केवल योजनाओं और निवेश के बल पर देश विविध चुनौतियों का सामना कर सकता है? समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए जरूरी है कि मौजूदा संस्थागत ढांचों की समीक्षा की जाए, जिससे वे नई चुनौतियों को हल करने में सक्षम हो सकें। शासकीय नीति तंत्र को बेहतर कार्य पद्धति के साथ विकसित करने, सुधार एजेंडे को समुचित स्वरूप देने एवं संवेदनशील अनुसंधान करने के लिए कौशल एवं व्यावसायिकता विकसित करने पर ध्यान देना आज एक बड़ी चुनौती है। शहरी विकास के मामले में विशिष्ट एवं समयबद्ध कार्यों के लिए बाहरी परामर्शदाताओं पर निर्भर रहने की जगह अब सरकारी तंत्र में परामर्शदाता फर्मों या थिंक टैंकों के अस्थायी विशेषज्ञ बढ़ रहे हैं। इससे शहरी मामले जटिल भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए थिंक टैंकों को और अधिक विश्लेषणात्मक कौशल से लैस होना होगा, क्योंकि सरकारी तंत्र का हिस्सा आवश्यक आंतरिक कौशल को विकसित करने के स्थान पर अस्थायी स्टाफ एवं बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर हो रहा है।

कुछ पेशेवर अक्सर संपूर्ण कार्यक्षेत्र का प्रबंधन करते हुए संस्थागत कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। स्टाफ की कमी और विस्तारित दायित्वों के कारणों से ऐसा और हो रहा है। निःसंदेह परामर्शदाताओं से सरकारी तंत्र को लाभ मिलता है, क्योंकि वे नीतियां बनाने के लिए सरकारी तंत्र को तकनीकी सलाह देने के साथ अन्य थिंक टैंकों के शोध निष्कर्षों को भी साझा करते हैं, जिससे बेहतर नीतियां बन पाती हैं, लेकिन इससे कुछ सरकारी विभागों की अपनी आंतरिक विशेषज्ञता समाप्त हो रही है, क्योंकि वे परामर्शदाताओं या अस्थायी विशेषज्ञों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। बाहरी विशेषज्ञों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता सरकारी तंत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता के लिए चिंताजनक है।

परामर्शदाता को किसी विशिष्ट कार्य के लिए एक निश्चित समयसीमा के लिए नियुक्त किया जाता है और कार्य की प्रगति के आधार पर उसे भुगतान किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बहुतेरे कार्यालयों में कई पेशेवर परामर्शदाता अस्थायी सरकारी कर्मियों की तरह काम करते हैं। प्रायः इन विशेषज्ञों के कार्यकाल भी बढ़ते रहते हैं। इससे वे दीर्घकालिक नीति-निर्माता बन जाते हैं। ऐसा ढांचा "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मंत्र से प्रेरित है, लेकिन यह ऐसी स्थिति की ओर भी ले जा रहा है जहां बाहरी विशेषज्ञ मुख्य कार्यबल को सहयोग देने के बजाय उनकी जगह ले रहे हैं। कुछ परामर्शदाता ऐसे कार्य भी करने लगे हैं जो स्थायी लोकसेवकों के जिम्मे होते हैं। यह स्थिति नियमित कर्मियों और बाहरी विशेषज्ञों के बीच संतुलन के बारे में कई प्रश्न उठाती है।

मुख्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार ऐसे स्थायी कर्मियों के पास ही होना चाहिए, जो जवाबदेह भी हों। आखिर स्थायी स्टाफ ही किसी विफलता या प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसेवकों का दीर्घकालिक अनुभव नीतिगत प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह विशिष्ट विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। खास परियोजनाओं में काम करने वाले विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं में इस व्यापक परिप्रेक्ष्य का अभाव हो सकता है। बाहरी विशेषज्ञता पर ब्रिटेन में 2021 में हुए एक शोध से पता चला कि परामर्शदाताओं पर अरबों खर्च किए गए, लेकिन इससे सरकारी कर्मियों को सीमित जानकारी ही मिल सकी। इसके बाद वहां परामर्शदाताओं की कार्य-अवधि की सीमा तय करने के उपाय हुए। दीर्घकालिक सफलता के लिए परामर्शदाताओं के ज्ञान एवं कौशल का हस्तांतरण आंतरिक कर्मियों को किया जाना महत्वपूर्ण है। मूल नीतिगत जिम्मेदारी स्थायी कर्मियों में ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारी संस्थाओं में अभी इस बारे में कोई मानक नियम नहीं कि परामर्शदाताओं को कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है?

क्या एक परामर्शदाता की कार्य अवधि तीन से पांच वर्ष होनी चाहिए? संवेदनशील डाटा संभालने या मंत्रिस्तरीय निर्णयों को प्रभावित करने वालों की नियुक्ति के पहले कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्या इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए कि उन पर खर्च का उचित प्रतिफल प्राप्त होने के साथ संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से हो पा रहा है या नहीं? आज के युग में सरकार की क्षमता के विकास के लिए इन जैसे प्रश्नों पर विचार हो, ताकि परामर्शदाता देश की प्रगति में अच्छे से सहायक बन सकें। उनकी विशेषज्ञता सरकारी तंत्र को विकसित करने की होनी चाहिए, न कि स्वयं तंत्र का रूप लेने की। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसे तंत्र की आवश्यकता है, जिनका नेतृत्व कुशल एवं स्थायी कार्यबल द्वारा किया जाता हो। भारत इस 'विशेषज्ञता के बंधन' से तभी उबर सकता है जब वह अपनी क्षमता निर्माण में व्यापक रूप से निवेश करे, बाहरी संस्थाओं की भूमिकाओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करे। हमें यह जानना होगा कि हमारी नीतिगत संस्थाओं का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में है और उसे किसके हाथ में होना चाहिए?

(वैद्य एनआइयूए के पूर्व निदेशक और मिश्र आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। आलेख में नीति आयोग के वरिष्ठ फेलो डा. ओपी अग्रवाल का विश्लेषणात्मक इनपुट भी शामिल है)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनंत चक्र

जीवन की चेतना जिस त्रयी में अनवरत प्रवाहि
होती है, वह है-सृजन, स्थिति और संहार। मू
अमूर्त कुछ भी इस नियम से परे नहीं है। सृज
अर्थात आदिशक्ति का प्रस्फुटन। यह वह बीज
जो ब्रह्मांड के विस्तार में जीवन को स्पंदन प्रद
करता है। यह केवल स्थूल शरीर का जन्म न
अपितु विचारों, कल्पनाओं, आकांक्षाओं और चैत
का भी प्रस्फुटन है। हर नवीन सृजन उसी ब्र
का विस्तार है। यह आत्मा के भीतर छिपी अप
सृजनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति है, जो ब्रह्म
इच्छा के अनुरूप जगत को रचती है।

स्थिति, सृजन का दूसरा चरण है। यह इस नश्
संसार में स्थायित्व और संतुलन लाती है। सृजन
भंगुरता से बचाकर उसे एक निश्चित समयाव
तक टिकाए रखती है। यहां जीवन रूपाकार ग्रह
करता है। अपनी सीमाओं और संभावनाओं
विस्तार करता है। यह स्थिति भी स्थायी न
क्योंकि जगत का एक अंतिम सत्य है परिवर्त
संहार जीवन के इस त्रिसूत्र का अंतिम चरण-प्रल
में विध्वंस, परंतु ब्रह्म की लीला का एक अंग।
यह विनाश नहीं, पुनर्निर्माण का आधार है। सं
के बिना नवीन सृजन असंभव है। यह चेतना
वह स्वर है, जो कहता है कि जीवन की गति केव
स्थायित्व में नहीं, उसका क्षरण ही पुनः उत्कर्ष है

इन अवस्थाओं को सहजता से स्वीकार कर
हर परिवर्तन को आत्मसात करना चाहिए। इन ती
में से किसी एक चरण के साथ तादात्म्य स्थापि
करके उसे जीवन की स्थायी अवस्था मान लेना
दुख का मूल कारण है। प्रकृति की विराट योजना
अवलोकन करने के लिए हमें संकीर्णता से ऊ
उठना होगा। यह त्रयी सृजन-स्थिति-संहार, जीव
की अनंत यात्रा का रहस्य है और यात्रा में पड़
आते हैं, ठहराव नहीं आते।

ट्विंकल तोमर सि

नवाचार में महिलाओं की सीमित भागीदारी

सोनम लववंशी

लड़कियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि मौजूदा सामाजिक बाधाएं और आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे धकेल देती हैं

यूनस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या महज 35 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा लगभग स्थिर बना हुआ है। यह स्थिरता दरअसल एक ठहरे हुए सोच और संरचनात्मक विषमताओं का परिणाम है, जिसे तोड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में प्रतिभा की कमी है, बल्कि उनके सामने मौजूद सामाजिक बाधाएं, रूढ़िगत धारणाएं और आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे धकेल देती हैं। जब एक लड़की विज्ञान या गणित में रुचि दिखाती है, तो पारिवारिक या सामाजिक माहौल उसे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के बजाय संशय में डाल देता है। लड़कियों के लिए कला विषय अधिक उपयुक्त हैं ऐसी धारणाएं अभी भी हमारे मन-मस्तिष्क में गहराई से जमी हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा विज्ञान और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक विषयों में भी महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। यूनस्को के आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 26, 15 और 12 प्रतिशत ही है।

भारत जैसे देश, जहां शिक्षा तक पहुंच एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, वहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा में लैंगिक असमानता और भी गहरी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य विज्ञान संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी 10-20 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। इसका कारण बालिकाओं को आरंभिक स्तर से ही वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में प्रशिक्षित न किया जाना भी है। महिलाओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भागीदारी सिर्फ एक लैंगिक संतुलन का प्रश्न नहीं, बल्कि नवाचार की समग्रता का मुद्दा है। विविधता से ही रचनात्मकता का जन्म होता है। जब विज्ञान में महिलाएं शामिल होती हैं, तो वे समाज के उन पहलुओं को भी संबोधित करती हैं, जिन्हें पारंपरिक पुरुष-दृष्टिकोण नजरअंदाज कर देता है जैसे स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव।

इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएं, जिनका उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना हो। छात्रवृत्तियों, मेंटरशिप प्रोग्राम और रिसर्च इंटर्नशिप जैसे अवसरों को विशेष रूप से लड़कियों के लिए सुलभ बनाना चाहिए। यदि हम एक समावेशी, नवाचारी और उत्तरदायी भविष्य की परिकल्पना करते हैं, तो उसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना ही एकमात्र रास्ता है। जब तक हम सोच में लैंगिक समता नहीं लाएंगे, तब तक विज्ञान अधूरा रहेगा। और अधूरा विज्ञान कभी संपूर्ण मानवता की सेवा नहीं कर सकता।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

समग्रता में समझना होगा संदेश

'लक्ष्य का संधान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बिल्कुल सही टिप्पणी की गई है कि किसी भी संघर्ष में अंतिम परिणाम ही मायने रखता है। सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद जिस तरह से विवाद खड़ा करने और एक विशेष नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह उचित नहीं। किसी भी परिपक्व एवं जिम्मेदार सैन्य प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी रण में अपनी गलतियों को चिह्नित कर उनके परिमार्जन का यथासंभव प्रयास करे। भारतीय सेनाओं ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जनरल चौहान ने वही बात दोहराई, जो इससे पहले वायुसेना अधिकारी भी आपरेशन सिंदूर के बाद कह चुके थे। युद्ध के दौरान हर पक्ष को कुछ न कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है। रूस और यूक्रेन की सामरिक क्षमताओं में जमीन-आसमान का अंतर है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी न तो यह युद्ध समाप्त हो पा रहा है और रूस को भी रह-रहकर क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए आपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या खोया से अधिक यह महत्वपूर्ण है कि उसने क्या पाया? वास्तव में आपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपने सभी लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए अपनी बढ़त को और निर्णायक रूप से स्थापित किया। जहां तक क्षति उठाने के मामले में पारदर्शिता को लेकर सवालों की बात है तो यह भी सोचा जाए कि इससे कहीं दुश्मन के नैरेटिव को मदद न मिले। हमें समग्रता में इसे समझना होगा। जनरल चौहान ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोलकर उचित ही किया। हालांकि साक्षात्कार के लिए किसी संस्था के चयन से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

पुनीत कश्यप, नई दिल्ली

मेलबाक्स

भारत की बढ़ती ताकत

सच यह है कि भारत की बढ़ती ताकत से अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देश चिंतित हैं। भारत विकास के क्षेत्रों में भी लंबी छलांगें मार रहा है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना, रेल एवं सड़क नेटवर्क के अभूतपूर्व विस्तार, सैनिक साजो-सामान के स्वदेशीकरण, गति शक्ति और आयुष्मान जैसी तमाम योजनाएं आदि शामिल हैं। कई आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था के चौथे पायदान पर पहुंच गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत का स्थान आ पहुंचा है। भारत की रफ्तार ऐसे ही बनी रही, तो दो-तीन साल के भीतर जर्मनी को पछाड़ कर तीसरी अर्थव्यवस्था का सिरमौर बन सकता है। भारत अब हाथ फैलाने वाला नहीं रह गया है, बल्कि जरूरतमंद देशों को सबसे पहले बढ़-चढ़कर मदद करने वालों में शुमार है। तुर्किये, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि अन्य कई देशों को भारत ने रसातल में जाने से बचाया है। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को दिक्कत यह है कि उन्हें पहले जैसा पिछलग्गू भारत नहीं मिल रहा है। भारत ने तेजी के साथ विकास की रफ्तार पकड़ी है। आज पूरी दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। भारत की विदेश नीति में अद्भुत बदलाव हुआ है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

आगे बढ़ने के लिए परिश्रम जरूरी

मेधा और कर्मठता जीवन की ये दो प्रमुख शक्ति
हैं। मेधा को हम बुद्धि कह सकते हैं। ज्ञान करने
समझने की शक्ति ही बुद्धि है। सारे सिद्धांत बौद्धिक
की देन हैं, सारी व्याख्याएं भी मेधा प्रस्तुत करती
किंतु सिद्धांतों और व्याख्याओं को रचनात्मक स्वरू
प्रदान करने का जहां तक प्रश्न है, वह कर्मठता
ही होता है। बौद्धिकता मस्तिष्क का कार्य है, कि
कर्मठता शरीर के सारे अंगों की सार्थकता है। कर्मठ
का दिशा-निर्देशन मस्तिष्क करता है, किंतु लक्ष्य त
पहुंचने का कार्य कर्मठता करती है। सारी श्रेष्ठत
जितनी भी उपलब्ध हैं, वे कर्मठता की देन
कर्मठता अर्थात कार्य करने की शक्ति। भारत सदि
से जीवन की समस्त शक्तियों का सर्वाधिक सदुपय
करने वाला राष्ट्र रहा है, किंतु पिछली दस शताब्दि
से इसकी कर्मठता में कुछ क्षीणता आई, उसके का
चाहे कुछ भी रहे हों, किंतु उस क्षीणता का परिण
क्रमशः पराधीनता के रूप में सामने आया।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

11,414 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं भारत की तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) में। यह आंकड़ा एक जनवरी, 2023 तक का है।

प्रियम वर्मा
priyammj22@gmail.com

आजकल

लैंगिक समानता का अहम सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सेना की कानूनी शाखा (जज एडवोकेट जनरल) में महिला अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने सेना में महिलाओं तथा पुरुषों की 50:50 चयन नीति पर आपत्ति जताई है। देश की शीर्ष अदालत के इस रुख से यह समझ आता है कि इस मामले में आरक्षण का फायदा महिलाओं नहीं, बल्कि पुरुषों को मिल रहा है। साथ ही इस वाकये ने महिला-पुरुष की बराबरी से लेकर महिलाओं को आरक्षण जैसी बहस को भी पीछे छोड़ दिया है

सेना में भी दमखम दिखाती महिलाएं। फाइल

पति की मौत के बाद 16 वर्षों तक राज संभालने वाली रानी दुर्गावती हों या शास्त्रार्थ के दौरान याज्ञवल्क्य को चुप कराने वाली ब्रह्मवादिनी गार्गी। भारत के झंडे को पहली बार विदेशी भूमि पर फहराने वाली मैडम भीकाजी हों या अपने संस्कृत के ज्ञान के चलते सरस्वती और पंडिता की उपाधि हासिल करने वाली समाजसेविका रमाबाई। इतिहास के ऐसे तमाम उदाहरण इस बात के गवाह हैं कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी, बल्कि उन्होंने तो सदियों पहले खुद को कई मायनों में सबसे बेहतर साबित किया है। आज एक बार फिर यह मुद्दा प्रासंगिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेना की कानूनी शाखा (जज एडवोकेट जनरल) में महिला अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर केंद्र से सवाल किया है।

दरअसल, शीर्ष अदालत ने सेना में महिलाओं और पुरुषों की 50:50 चयन नीति पर आपत्ति जताई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दो महिला अधिकारियों अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी की याचिका पर फैसला सुरक्षित करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जज एडवोकेट जनरल की परीक्षा में उनकी चौथी और पांचवीं रैंक आई थी, इसके बावजूद उनसे कम रैंकिंग वाले पुरुष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। याचिका में कहा गया है कि विभाग में सिर्फ छह पद निकले थे, जिनमें से महिलाओं के लिए तीन ही रिक्तियां थीं। जस्टिस दत्ता ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से पूछा, 'अगर भारतीय वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान राफेल उड़ा सकती हैं तो फिर सेना की जज एडवोकेट जनरल पदों पर ज्यादा महिलाओं को शामिल करना क्यों मुश्किल है?' इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता अर्शनूर कौर को सेना की कानूनी शाखा में शामिल करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता आस्था त्यागी ने भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कम पद निर्धारित किए हैं जबकि इन पदों को लैंगिक रूप से तटस्थ बताया गया है।

देश की सुप्रीम अदालत के इस रुख से यह तो समझ आ गया कि इस मामले में आरक्षण का फायदा महिलाओं नहीं, बल्कि पुरुषों को मिला। साथ ही इस वाकये ने महिला-पुरुष की बराबरी से लेकर महिलाओं को आरक्षण जैसी बहस को भी पीछे छोड़ दिया। बता दें, भारतीय सेना में महिला अफसरों के लिए 23 नवंबर, 2021 को एक जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोग्रेशन पालिसी लाई गई थी, जिसके बाद अब आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिटरी नर्सिंग सेवाओं के लिए 11 आर्म्स एंड सर्विसेज में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिलता है जिनमें जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के अलावा आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर, इलेक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल कोर, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, रीमाउंट एंड वेटनरी कोर आदि शामिल हैं।

कहने के लिए तो यह व्यवस्था हथियारों और सेवाओं में समान अवसर एवं तैनाती की बात करती है, लेकिन ऐसी भी कई घटनाएं हैं, जो महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी सीमित भागीदारी की तरफ भी इशारा करती हैं।

भारत की तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) में महिलाओं की संख्या को लेकर अगस्त 2023 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। थल सेना में 7,054 महिलाएं सेवारत हैं। इनमें 1,733 महिला अधिकारी हैं। यह आंकड़ा एक जनवरी, 2023 तक का है। भारतीय वायु सेवा में 1,654 अधिकारी सेवारत हैं जबकि 155 महिलाएं एयर मैन (अग्निवीर) के रूप में सेवा दे रही हैं। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत हैं जबकि 727 महिलाएं सैलर्स (अग्निवीर) के तौर पर तैनात हैं।

घोषित उदारवादी रवैये का इतिहास भी काफी पुराना है। मसलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, महिलाओं को सिर्फ नर्सों के तौर पर सैन्य अस्पतालों में शामिल किया गया था, वह भी इसलिए, क्योंकि तब पर्याप्त संख्या में पुरुष उपलब्ध नहीं थे। वहीं साल 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की एक सहायक कोर की स्थापना की भी गई तो इसलिए कि महिलाएं गैर-लड़ाकू और दफ्तर संबंधी भूमिकाओं में काम कर सकें। अभी भी महिलाएं थल सेना की कुछ मुख्य लड़ाकू भूमिकाओं में काम नहीं कर सकती हैं। इनमें पैदल सेना (इन्फैंट्री), बख्तरबंद (आर्मर) और मशीनीकृत इकाइयां शामिल हैं।

इसके बावजूद, भारत की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और थलसेना एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरीन भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए चिकित्सा सेवाओं के निदेशक जनरल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए अतिविशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं डीजी चिकित्सा सेवा (सेना) लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को राष्ट्रपति द्वारा एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायु कमान और चीफ आफ द एयर स्टाफ प्रशंसा के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पदक दिया जा चुका है। इसके अलावा नौसेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त कर चुकी हैं। वह इससे पहले सेना के चिकित्सा कोर में कर्नल कमांडेंट पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अफसर रह चुकी हैं।

ऐसे में साफ है कि जब महिला पुरुष का कोई मुकाबला ही नहीं है तो उनकी समानता या आरक्षण की बात क्यों की जाए? महिला-पुरुष दोनों समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और दोनों की अपनी-अपनी काबिलियत हैं तो उनका मुकाबला क्यों करवाया जाए। उनकी शारीरिक क्षमताओं की ही बात करें तो एनडीए (नेशनल डिफेंस एकेडमी) की तरह ओटीए (आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी) में महिला और पुरुष कैडेट के लिए अलग-अलग पैरामीटर हैं। पुरुष कैडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ नौ मिनट में पूरी करनी होती है और महिला कैडेट के लिए 11 मिनट का समय रहता है। वहीं बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जहां पुरुष कैडेट को 10 चिनअप्स करने होते हैं तो महिला कैडेट को इसकी जगह पर 20 पुशअप्स करने होते हैं।

हर मोर्चे पर खुद को साबित करती आधी आबादी

नियमों के अलावा कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां महिलाओं ने न सिर्फ पुरुषों की तुलना में खुद को कई गुना बेहतर साबित किया है, बल्कि उस क्षेत्र में इतिहास भी रच दिया है।

उदाहरण के तौर पर, कर्नल सोफिया को लोग भले ही आपरेशन सिंदूर से जोड़ कर देख रहे हों, लेकिन उनके संघर्ष और योग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में स्थाई कमीशन पर फैसले के दौरान सराहा था जिसमें महिलाओं को सिर्फ स्टाफ ड्यूटी तक सीमित रखना अनुचित बताया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में अधिकारी हैं, वर्ष 2016 में 'एक्सरसाइज फोर्स 18' नामक एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनीं।

फिर कारगिल युद्ध के दौरान शौर्य से निखरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और उनकी सहयोगी श्री विद्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। करीब तीन महीने बाद भारी कीमत चुकाकर भारत ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हमारे देश के लगभग 570 जवान शहीद हुए थे और कई घायल। वायुसेना ने इस दौरान आपरेशन सफेद चादर लांच किया जिसमें ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ी। इन दोनों को कारगिल में घायल जवानों को मदद पहुंचाने और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया था जिसे दोनों ने निभाया। इसके लिए गुंजन सक्सेना को शौर्य चक्र से नवाजा गया।

वहीं भारतीय वायु सेना की पहली महिला एयर मार्शल डा. पद्मावती बंदोपाध्याय एक ऐसा उदाहरण हैं जो शायद बाकी महिलाओं के साथ उनके पति एसएन बंदोपाध्याय के लिए भी प्रेरणा साबित हुईं। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और राष्ट्रपति सम्मान पदक सहित देश दुनिया के करीब एक दर्जन से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। ये एक ऐसा दंपती हैं जिन्हें विशिष्ट सेवा पदक एक ही दिन एक साथ दिया गया। 2020 में डाक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को पद्मश्री सम्मान मिला। इसके अलावा 21 सितंबर, 1992 को प्रिया झिंगन भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी थीं। इन्होंने ही सिर्फ पुरुषों के लिए विज्ञापन देखकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स को एक चिट्ठी लिखकर महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने की मांग की थी। इस मांग के बाद ही सेना में भर्ती होकर महिलाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया गया और आर्मी का रास्ता महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया।

ये तमाम नियम हैं और दर्जनों उदाहरण हैं जो महिलाओं की योग्यता की मौलिक कहानी बताते हैं। उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी ही नहीं, बल्कि समाज में उनकी अपनी अलग एक महत्वपूर्ण जगह है, ये उदाहरण साबित करते नजर आ जाते हैं। कई मामलों में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष अदालत हो या सरकार...सभी ने इसे सराहा और स्वीकारा है, स्वयं तो किसी से कम या बराबर आंकने का जिम्मा उन्होंने इस समाज को भी नहीं दिया है।

-प्रियम वर्मा

खरी-खरी

सबसे पहले बोलने वाले नेता जी

प्रकाश हेमावत

इन दोनों देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है। हर जगह, हर समय, इस स्वतंत्रता का उपयोग हो रहा है। हर क्षेत्र में बोलने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ज्ञानी और ध्यानी को यह समझ नहीं आ रहा है कि कब, कहां, कैसे और क्यों बोलना चाहिए। कहा जाता है कि आदमी बिना खाए रह सकता है, लेकिन बोले बिना नहीं रह सकता। मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जुबान को नहीं रोका जा सकता।

देश में किसी भी घटना पर बोलने वालों की लंबी कतार लगी है। बोलने वाला भूतकाल के परिणामों को भूल जाता है और वर्तमान को स्वार्थ की दृष्टि से देखता है। वह भविष्य की चिंता किए बिना बोल देता है। किसी चर्चित व्यक्ति के एक बार बोल देने के बाद प्रतिक्रिया देने वालों की बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में यह नहीं देखा जाता कि किसका कितना नुकसान हुआ है। बोलने वाले यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि सभी को बोलने का अधिकार है।

आज के समय में, जब सूचना का प्रवाह इतना तेज है, तब बोलने की प्रवृत्ति ने एक नई दिशा ले ली है। इंटरनेट मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि लोग लोकप्रियता पाने के लिए भी कई बार अपनी बातों को बिना विचारे साझा कर देता है। यह प्रवृत्ति न केवल समाज में असंतुलन पैदा कर रही है, बल्कि यह विचारों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही है।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम बोलने से पहले सोचें और अपने शब्दों के प्रभाव को समझें। कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। चाहे समय कैसा भी हो, चुप रहकर भी शोर मचाया जा सकता है। क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए सोच-समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि फिजूल बोलने से स्थिति बिगड़ सकती है। मौन कई सवालों का समाधान करता है। इसलिए बोलने वाले सजग और सावधान रहें। इसी में भलाई है।

पोस्ट

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले की इंडोनेशिया में तारीफ की है। कांग्रेस पार्टी आखिर कहां-कहां किस-किस को रोके?

पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

किसी भी नेता के विरोध में राष्ट्र-विरोधी मत बन जाइए। भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना या उस ओर बढ़ना कोई बड़ी खबर नहीं है। यह तो होना ही है। तीसरे नंबर तक की यात्रा तो जल्द ही पूरी होकर रहेगी। आने वाले दिनों में वह शुभ समाचार भी आएगा। हमारी दिशा कुल मिलाकर सही है। इसलिए, मोदी विरोध में राष्ट्र विरोधी मत बनिए।

दिलीप मंडल@Profdilipmandal

भारत के विमान गिरे या नहीं गिरे, लेकिन यह सच्चाई एकदम साफ है कि आपरेशन सिंदूर में सभी लक्ष्यों की पूर्ति हुई। नस्लीय मानसिकता वाला पश्चिमी मीडिया अपनी आदत के अनुसार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा है। पूरा नैरेटिव यही कहानी बनाने से जुड़ा है।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की जीडीपी विकास दर संतोषजनक है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि शेख हसीना को दोषी ठहराए जाने के बाद बांग्लादेश में अशांति और बढ़ेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कितना पाकिस्तान का किया गया नुकसान,
इसे छोड़ राफेल पर खींच रहे वे कान!
खींच रहे वे कान युद्ध है मेरे भाई,
हुए बिना नुकसान न होती खत्म लड़ाई।
हंसता पाकिस्तान पड़ा है जिसको पिटना,
जब जयराम रमेश पूछते कितना-कितना!!

- ओमप्रकाश तिवारी

अजय जायसवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख

उत्तर प्रदेश डायरी

पंचायत चुनाव के लिए छोटे दलों का बड़ा 'दांव'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों में बड़ा बनने की छटपटाहट दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन में हिस्सेदारी मांगने की भूमिका बनाने वाले जातीय राजनीति के क्षेत्रीय 'पहलवान' अब पंचायत चुनाव के बहाने बड़ा बनने का 'दांव' चलते दिखाई दे रहे हैं। लगभग दो वर्ष बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगले वर्ष अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में बड़े दलों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने वाले ज्यादातर छोटे दलों ने त्रिस्तरीय चुनावों में अकेले दम पर उतरने की घोषणा की है। सबसे पहले अपना दल सोनेलाल ने बिना गठबंधन में चुनाव में उतरने की बात कही। फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) ने भी अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।

हालांकि इन छोटे दलों ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बरकरार रखने की बात कही है। वास्तव में इन दलों का लक्ष्य गठबंधन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी पाने की ही है और पंचायत चुनाव को इसके लिए दबाव बनाने के हथियार के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की इच्छा अकेले एनडीए के घटकों में ही नहीं है, बल्कि आइएनडीआइए गठबंधन में भी यह जिद्दोजहद लोकसभा चुनाव के बाद से ही जोरों पर चल रही है और अब कांग्रेस ने सपा से अलग अकेले ही पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस और एनडीए के घटक दलों की चाहत चाहे जो हो, लेकिन अभी तो न भाजपा और न ही सपा उनकी घोषणाओं को भाव देते दिख रही है। दोनों ही दल फिलहाल अलग चुनाव लड़ने की बात करने वाली पार्टियों के सीमित दमखम

अनुप्रिया पटेल फाइल

ओमप्रकाश राजभर फाइल

संजय निषाद फाइल

और अपनी मजबूत स्थितियों के हिसाब से बेफिक्री जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव नजदीक आने तक दबाव और बेफिक्री का यह खेल जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनावों में 58,189 ग्राम पंचायत और 826 ब्लाक थे। 107 नई नगर पंचायतों के गठन के चलते लगभग 500 ग्राम पंचायतों को नगरीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2026 के चुनाव के लिए चल रही परिसीमन की प्रक्रिया में 500 नई ग्राम पंचायतें और 75 नए ब्लाक बढ़ सकते हैं। पार्टी सिंबल पर न होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल सीधे तौर पर भूमिका नहीं निभाता और अपनी विचारधारा वाले सभी प्रत्याशियों के लिए तटस्थ रहता है। वहीं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में ये चुने हुए प्रतिनिधि वाली भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव के लिए आधार तय करने वाला माना जा रहा है। ऐसे में छोटे दलों को भी ये चुनाव शक्ति प्रदर्शन और दबाव की रणनीति का अवसर नजर आ रहे हैं, लेकिन वे भाजपा के साथ की ताकत को भी ठीक से पहचानते हैं। यही वजह है कि पंचायत में अकेले लड़ने की बात कहने के साथ गठबंधन के बरकरार रहने की भी दुहाई दी जा रही है। अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल ने इस चुनाव के लिए गठबंधन पर बात न होने की बात कह दरवाजा खोले रखा है। सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर भी यही रुख दिखा रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने तो साफ कहा है कि निषाद बाहुल्य क्षेत्रों में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर प्रत्याशी लड़ाएंगी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख पद के लिए भाजपा को समर्थन देंगे।

साफ है कि छोटे दलों को बखूबी पता है कि यदि गठबंधन से बाहर गए तो सत्ता की मौजूदा हिस्सेदारी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भाजपा की बेफिक्री का यह भी एक बड़ा कारण है। वहीं कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने को लेकर सपा के नेतृत्व को भी कोई आश्चर्य होता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पहले से ही अपनी अलग तैयारी में जुटी है और सपा से कई बार बयानों की तकरार भी हो चुकी है। ऐसे में सपा नेतृत्व भी ताजा घोषणा से खुद को अप्रभावित दिखा रहा है। हालांकि भाजपा और सपा अभी पंचायत चुनावों के नजदीक आने का इंतजार कर रही हैं। चुनावों से ऐन पहले इस बात का आकलन किया जा सकता है कि उनके गठबंधन के सहयोगियों के अलग लड़ने से क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा? पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद एनडीए गठबंधन अब कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन छोटे दलों के अलग-अलग और भाजपा के ही सामने मैदान में उतरने से विभिन्न वर्गों के मतों की गोलबंदी की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ डायरी

शांति, सुरक्षा और विकास

डा. सुनील गुप्ता
संपादकीय प्रभारी,
बिलासपुर

छत्तीसगढ़, जो कभी माओवादी हिंसा और असुरक्षा का पर्याय माना जाता था, आज शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा से मुक्ति के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यापक रणनीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। माओवादी हिंसा के उन्मूलन की दिशा में सुरक्षा बलों ने अद्वितीय साहस, क्षमता और शौर्य का परिचय दिया है। हाल में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में, जो कभी माओवादियों का मजबूत गढ़ था, सुरक्षा बलों ने भीषण गर्मी के बीच बड़ा अभियान चलाकर 27 माओवादियों को मार गिराया और माओवादी सरगना बसव राजू को ढेर कर एक बड़ी सफलता हासिल की। इस क्षेत्र में 200 से अधिक बंकरों में गोला-बारूद और हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह माओवादी नेटवर्क का प्रमुख संचालन केंद्र था। सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता, अनुशासन और संकल्प के परिणामस्वरूप यह दुर्गम इलाका अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। यह घटना केवल एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की निर्णायक शुरुआत का संकेत है।

पिछले 16 महीनों में 420 माओवादी मारे गए, जबकि माओवादी संगठनों के अनुसार यह संख्या 448 तक पहुंचती है। 1,402 माओवादी गिरफ्तार किए गए और 1,367 ने आत्मसमर्पण किया। मुठभेड़ों के दौरान 443 हथियार जब्त किए गए, जिनमें एके-47, इंसास और 303 राइफलें प्रमुख हैं। यह सब माओवाद के विरुद्ध चल रहे अभियान की सफलता का प्रमाण है।

राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नियद नेल्ला नार योजना और जंगलों में सुरक्षा बलों की बढ़ती उपस्थिति के चलते माओवादियों में आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति तेज हुई है। यह स्पष्ट संदेश दिया गया है या तो आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौट आओ या फिर सुरक्षा बलों की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहो। इस योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। बस्तर, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में आत्मसमर्पण की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव वहां की जनता के बदलते सोच और शांति की आकांक्षा को दर्शाता है। हाल में 'सुशासन तिहार' के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित शिविर में शामिल हुए और विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य विज्ञानियों द्वारा विकसित उन्नत कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना है। अब तक 13 लाख से अधिक किसान इस अभियान से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि को समृद्धि का आधार बनाकर राज्य सरकार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

बस्तर में माओवादी हिंसा का अंत अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी आशाजनक पहल है। सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सम्मान दिया है। वहीं बैगा, गुनिया और सिरहा जैसे पारंपरिक जनजातीय समुदायों को हर वर्ष 5,000 की सम्मान निधि देकर उनकी सांस्कृतिक पहचान को संजोने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बलिदानी आदिवासी सेनानियों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जा रही हैं, जो केवल स्मृति नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य भी कर रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं अब बस्तर जैसे माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और समृद्धि की नई लहर ला रही हैं। यदि यह रफ्तार बनी रही, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ न केवल माओवादी हिंसा से मुक्त होगा, बल्कि एक आदर्श व आत्मनिर्भर राज्य के रूप में देश के सामने मिसाल भी पेश करेगा।

माओवादियों से जूझते जवानों का उत्साहवर्धन करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। फाइल

बस्तर केवल प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध लोककला और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य सरकार इस सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में कार्य कर रही है। कहीं न कहीं माओवादी हिंसा उनके इस कार्य में बाधक बनी हुई थी। संस्कृति विभाग को वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, ताकि वह उन्मुक्त वातावरण में कोई सार्थक पहल कर सके। इसके बाद भी वहां बस्तर आर्ट, काष्ठशिल्प, लौहशिल्प, झिटकूमिटकी कला जैसे पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही थी, जिससे स्थानीय कारीगरों को आधुनिक तकनीकी सहायता, डिजाइन इनोवेशन और विपणन के अवसर मिल सकें। साथ ही ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से इन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद न केवल बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग भी मिलेगा। हिंसा मुक्त वातावरण वाले आत्मनिर्भर बस्तर के सपने को साकार करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा।

बांग्लादेश में संकट

बढ़ती अराजकता

बांग्लादेश में संकट गहराता जा रहा है क्योंकि प्रमुख पक्ष शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं जिससे अराजकता बढ़ रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक बारूद सुलग रहा है जिससे न केवल देश के स्थायित्व पर खतरा है, बल्कि इसकी छाया भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम काल में गैर-निर्वाचित सलाहकार नेता मुहम्मद यूनुस तथा सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा के नेतृत्व में देश की सेना के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। संकट के केन्द्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विखंडन, तेजी से बिगड़ता सुरक्षा परिवेश तथा भू-रणनीतिक परिवर्तन है जिसके प्रभाव बांग्लादेश की सीमाओं से बहुत आगे तक जाएंगे। मुहम्मद यूनुस ने स्वयं को शुरुआत में केवल अस्थाई सलाहकार के रूप में पेश किया, लेकिन अब उन्होंने बिना किसी व्यापक जनादेश के सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया है। चुनाव कराने में उनकी अनिच्छा तथा प्रशासन की लगातार उग्र व विदेशोन्मुख प्रकृति का देश की राजनीतिक शक्तियों तथा सेना की ओर से भारी विरोध हो रहा है। यूनुस द्वारा चुनावों की घोषणा में अनिश्चित विलंब से निराश जनरल वकारुज्जमा ने संवैधानिक व्यवस्था लौटाने की मांग की है। उन्होंने घोषणा की है कि सेना की भूमिका देश की रक्षा करना है, पुलिस जैसा कामकाज करना नहीं। बांग्लादेश के काक्स बाजार से म्यांमार के राखीन राज्य तक अमेरिका-समर्थित विवादास्पद 'राखीन कॉरीडोर' का मुहम्मद यूनुस द्वारा समर्थन से तनाव विस्फोटक बिंदु तक पहुंच गया। हालांकि, इसे मानवीय सहायता के नाम पर पेश किया गया, पर सेना इस कॉरीडोर को संभावित भू-राजनीतिक जाल मानती है। इसके माध्यम से बांग्लादेश में छद्म युद्ध शुरू हो सकता है, उसकी संप्रभुता प्रभावित हो सकती है तथा वह क्षेत्रीय टकरावों में फंस सकता है।

यूनुस के विदेश नीति झुकाव से बांग्लादेश का आंतरिक संकट खतरनाक रूप से अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल सकता है। इस नीति में बांग्लादेश के हितों के बजाय सत्ता पर उनको अपनी पकड़ मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। चीन और पाकिस्तान को खुश करने, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लालमोनीरीहाट हवाईअड्डा बीजिंग को सौंपने तथा अमेरिकन हितों के प्रति झुकाव के कथित प्रयास बांग्लादेश के परंपरागत रूप से भारत से जुड़ाव तथा उसके गठन के मूल सिद्धान्तों से व्यापक विचलन का संकेत देते हैं। विश्व नेताओं के सहयोग से अपनी गैर-निर्वाचित सरकार को वैधता दिलाने तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही से पल्ला झाड़ने के परोक्ष प्रयास संभवत: सर्वाधिक परेशान करने वाले हैं। यूनुस ने अमेरिका से लेकर वेटिकन तक कई देशों की यात्रा की है और वे देश में अस्वीकृति के बावजूद विश्व मंच पर अपनी वैधता तलाश रहे हैं। यूनुस का समर्थन कर रही जमात जैसी इस्लामवादी शक्तियां और देश की प्रमुख सेक्युलर पार्टी-अवामी लीग पर प्रतिबंध से धार्मिक पुन: ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ गया है। भारत के लिए यह स्थिति बहुस्तरीय चुनौतियां पेश करती है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के क्षरण, मुहम्मद यूनुस की भारत-विरोधी लफ्फाजी तथा उनके चीन और पाकिस्तान के प्रति झुकाव से नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। ढाका में जो कुछ भी होता है, वह केवल ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश में आंतरिक संघर्ष व्यापक भू-राजनीतिक टकरावों और वैचारिक संघर्षों से भी प्रभावित है जो पूरे दक्षिण एशिया पर असर डाल रहे हैं। बांग्लादेश में यह समय लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए जागरूक और सतर्क होने का समय है। भारत समेत सारी दुनिया को बांग्लादेश की स्थितियों पर सावधानी से नजर रखने के साथ ही वहां पैदा हो रही विकृतियों के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हालांकि, भारत सरकार द्वारा लगातार दबाव डालने से बांग्लादेश में हिंदू-विरोधी हिंसा काफी सीमा तक थमी है, पर उनका अलगाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश की जनता को अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार है जिसमें किसी प्रकार का षडयंत्र, सैन्यवाद या विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में आगे बढ़ने का रास्ता केवल मतपेटियों से होकर गुजरता है।

बांग्लादेश में विस्फोटक स्थिति

बांग्लादेश में स्थिति विस्फोटक है। राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है तथा चुनाव टालने के प्रयासों से षडयंत्र की आशंका है। राजनीतिक दल जल्द चुनाव कराने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिससे अराजकता और बढ़ेगी।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

क्या बांग्लादेश में स्थितियां विस्फोटक हो रही हैं? 28 मई, 2025 को 'द डेली स्टार' की एक रिपोर्ट के अनुसार चार दिवसीय जापान यात्रा पर आए मुहम्मद यूनुस ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-बांग्लादेश संसदीय मैत्री लीग के अध्यक्ष तारो आसो से कहा कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसद के चुनाव किसी भी परिस्थिति में जून, 2026 तक करा लिए जाएंगे। मुख्य सलाहकार के रूप में मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिम प्रशासन तीन प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

इसमें सुधार, राजनीतिक हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई तथा आगामी राष्ट्रीय चुनाव शामिल हैं। इसी दिन के 'ढाका ट्रिब्यून' के अनुसार, यूनुस की भावनायें प्रकट करते हुए प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने तारो आसो से बैठक के बाद कहा कि यूनुस तीन खास एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनमें सुधार, फासिस्ट तत्वों के खिलाफ मुकदमा तथा चुनाव शामिल हैं, 'सब कुछ ठीक होने के बाद वे चुनाव तिथियों की घोषणा करेंगे।' दूसरी और लंदन से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी के तीन मोर्चा संगठनों-छात्र दल, युवा दल और स्वेच्छासेवक दल द्वारा आयोजित रैली को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 28 मई को कहा, 'हम अंतरिम सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर के अंत तक कराए जाएं।'

चुनावों को 'इस समयसीमा के भीतर' कराने पर जोर देते हुए उन्होंने अपने 'प्रिय देशवासियों' से पूछा कि क्या वे यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर तक हो जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर कुछ तत्व चुनावों में विलंब करने का षडयंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव रोकने के प्रयास शुरू हो गए हैं। चुनावों के भविष्य को तथाकथित मामूली और बड़े सुधारों की अंतहीन बहसों में उलझा दिया गया है। लोग यह विश्वास करने लगे हैं कि सुधारों पर यह चर्चा केवल समय बिताने की रणनीति है और अंतरिम सरकार के भीतर और बाहर के कुछ तत्वों के निहित स्वार्थ हो सकते हैं।' इसके पहले ढाका में 25 मई, 2025 को नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की 18वीं वर्षगांठ पर एक वर्चुअल चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने सरकार की रचनात्मक आलोचना की बात कही थी, चाहे वह निर्वाचित सरकार हो अंतरिम सरकार या कामचलाऊ सरकार।

देश की जनता सरकार की दया पर निर्भर नहीं है जिसे उनकी वैध मांगें अवश्य पूरी करनी चाहिए। बांग्लादेश के प्रमुख बांग्ला दैनिक 'प्रथम आलो' के अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने विभिन्न श्रेणियों के सेनाधिकारियों की एक बैठक को 21 मई, 2025 को संबोधित करते हुए कहा था कि अगले राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर 2025 तक हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है और देश का भावी रास्ता तय करने के लिए एक निर्वाचित सरकार के अधिकार पर उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनरल वकारुज्जमा ने यह भी कहा था कि छत्तोग्राम में नए मूरिंग कंटेनर टर्मिनल को विदेशी उद्यमों को सौंपने का निर्णय राजनीतिक सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए और उसे ही म्यांमार के राखीन प्रांत में लोगों की सहायता के लिए मानवीय कॉरीडोर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। बहु-प्रचारित सुधारों के बारे में उन्होंने कहा था कि उनसे इस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई है। 28 फरवरी, 2025 को शेख हसीना के तख्तापलट में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले छात्रों ने 'नेशनल सिटीजन पार्टी' का गठन किया था जो चुनाव करवाने की जल्दी में नहीं लगती है। 17 अप्रैल, 2025 को 'द डेली स्टार' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के समन्वयक नाहीद इस्लाम ने ढाका में 16 अप्रैल को प्रेस को बताया कि प्रशासन बीएनपी की सहायता कर रहा है और उसके अंतर्गत स्वतंत्र एवं मुक्त चुनावों की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी मूलभूत सुधारों के पक्ष में है जिससे देश में गुणात्मक परिवर्तन आएं।

बिना ढांचागत परिवर्तन क देश में चुनावों की दिशा में आगे बढ़ना खतरनाक होगा और उनकी पार्टी ऐसे चुनाव में भाग लेने या न लेने का निर्णय करेगी। 21 अप्रैल, 2025 को 'द डेली स्टार' में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में एनसीपी के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बांग्लादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने के बाद कहा था कि चुनाव सुधारों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए जो संभवत: मुहम्मद यूनुस द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार ही संभव है। अन्य एनसीपी नेताओं ने कहा था कि चुनाव केवल शेख हसीना तथा अन्य अवामी लीग नेताओं की सुनवाई और दंड के बाद ही कराए जाने चाहिए जिनको वे 'जनता के हत्यारे' घोषित कर चुके हैं।

इस प्रकार चुनावों के समय के बारे में देश में दो विपरीत दृष्टिकोण हैं जिनमें से एक का प्रतिनिधित्व यूनुस और छात्र नेता तथा दूसरे का बीएनपी व बांग्लादेश सेना करते हैं। जमाते इस्लामी बांग्लादेश एक समय बीएनपी के अत्यधिक निकट रही है और उसके बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में दो मंत्री थे, लेकिन अब उसका झुकाव मुहम्मद यूनुस ी ओर है। उसने कहा है कि अगले संसदीय चुनावों के समय के बारे में वह मुहम्मद यूनुस के विचारों से सहमत है। इस प्रकार अन्य कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक संगठनों तथा पार्टियों, जैसे हिफाजते इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के निकट संपर्क वाली यह पार्टी अपने विकल्प खुले रखना चाहती है। दूसरी ओर मुहम्मद यूनुस, बीएनपी और सेना के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं लगते हैं।

अंतरिम सरकार में मुहम्मद यूनुस से जुड़ी सलाहकार परिषद तथा नेशनल सिटीजन पार्टी एकसाथ हैं। इस प्रकार चीजें असहज स्थितियों की ओर बढ़ रही हैं। 'ढाका ट्रिब्यून' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी अध्यक्ष की सलाहकार परिषद के सदस्य जैनुल आबेदीन फारूक ने 12 मार्च, 2025 को ढाका में एक रैली में कहा कि नई पार्टी-एनसीपी अब 'चुनाव टालने के लिए अराजकता पैदा कर रही है और लोगों ने यह बात कहना शुरू कर दी है।' 18 अप्रैल, 2022 को ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए बीएनपी के उपाध्यक्ष शमशुज्जमा दुदू ने दावा किया कि अंतरिम सरकार चुनावों में विलंब कर रही है ताकि बीएनपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। ऐसे में यह देखना होगा कि यदि अंतरिम सरकार दिसंबर, 2025 तक चुनाव कराने से इनकार कर दे तो बीएनपी और सेना क्या करेगी? क्या बीएनपी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी? क्या सेना मुहम्मद यूनुस पर दबाव डालने का प्रयास कर सकती है? ऐसा लगता है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस भी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।

बताया जाता है कि 21 मई, 2025 को उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वे बांग्लादेश की वर्तमान स्थितियों में काम नहीं कर पा रहे थे और राजनीतिक पार्टियां देश में परिवर्तन के लिए समान आधार तैयार करने में विफल रही थीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला और वे पद पर बने हुए हैं। चुनावों की मांग और सेना से तनाव जारी है। इसके बाद अचानक 24 मई को ढाका में सलाहकार परिषद की बैठक हुई जिसमें अतार्किक मांगों, अनाधिकृत और राजनीति से प्रेरित बयानों तथा विघटनकारी कार्यक्रमों के माध्यम से कर्तव्यों में बाधा डालने के प्रयासों पर चिन्ता प्रकट की गई। इसमें चेतावनी दी गई कि यदि पराजित शक्तियों तथा विदेशी षडयंत्रों से प्रेरित ये बाधायें बनी रहीं तो सरकार का काम करना असंभव हो जाएगा।

ऐसी स्थिति में वह सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी तथा जनता की साझेदारी से निर्णय लेगी। परिषद ने कहा कि अंतरिम सरकार जुलाई विद्रोह की भावना और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यदि उसकी स्वतंत्रता, सुधार के प्रयासों, न्यायिक प्रक्रिया तथा स्वतंत्र चुनाव के प्रयासों को लगातार धक्का दिया गया तो सरकार जनता का समर्थन प्राप्त करने तथा सभी आवश्यक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी।

इस संदेश से स्पष्ट है कि 'जन समर्थन' लेने के नाम पर देश भर में हिंसा और टकराव पैदा हो सकता है। सवाल है कि क्या जुलाई, 2024 में शेख हसीना और अवामी लीग को सत्ता से हटाने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और सेना इस स्थिति में व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या करेगी? बांग्लादेश का भविष्य इन सवालों के जवाब पर निर्भर करेगा।

बदलती विश्व व्यवस्था में भारत

"एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत के उदय ने मौजूदा शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया है।"

बंशीधर रुखइयार
(लेखक, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)

पिछले छह वर्षों में हमारी आंतरिक और बाह्य नीति में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसने न केवल हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। यह सब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ शुरू हुआ। यह एक बड़ा फैसला था जिसे बिना किसी हो-हल्ले के अत्यंत शानदार ढंग से लागू किया गया।

दुनिया ने भी इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और देश में लोगों का एक छोटा समूह जो छोटी-छोटी बातों पर बवाल मचाने में माहिर है, पूरी तरह से हैरान रह गया और वह उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सका जैसा कि वह करने के लिए जाना जाता है। दूसरी घटना कोविड-19 का प्रकोप था, जिसने भारत और बाकी दुनिया को भारी झटका दिया। सभी ने सोचा कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और मृत्यु दर अकल्पनीय होगी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन और संपत्ति के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हम प्रलय की सभी भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए, बहुत शानदार तरीके से इससे बाहर निकले। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया और उन देशों की मदद की, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी।

इसने एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में हमारी छवि को आकार देने में बहुत मदद की, क्योंकि भारत ने उन्हें मुफ्त में और बिना किसी लाभ की उम्मीद के मदद की, और वह भी ऐसे माहौल में जब स्वीकार किए गए वैश्विक नेता त्रासदी और आघात की उस घड़ी में अपना हक पाने के लिए गिद्धों की तरह व्यवहार कर रहे थे। सलामी स्लाइसिंग की चीनी नीति और गलवान घाटी में उनके दुस्साहस का असाधारण समाधान किया गया, और लद्दाख सीमा पर चीन के साथ हमारा लंबा गतिरोध रहा। अंत में, दोनों देश तनाव कम करने और सेना हटाने पर सहमत हुए, और शांति बहाल हुई। यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी, और दुनिया यह जानकर खुश थी कि कोई चीन का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है। यह चीनी आधिपत्य में एक बड़ी सेंध थी। चौथी घटना रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने से हमारा कड़ा इनकार था।

हमने रूस से विशेष छूट वाली दरों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जिससे हमारे आंतरिक बाजार को कच्चे तेल की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव से बचाया जा सका। हमने उन्हें रिफाइन करके और यूरोप को बेचकर भी बहुत सारा पैसा कमाया। यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। भारत ने एक मजबूत रीढ़ दिखाई, जो उसकी नई ताकत और स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर, नवीनतम घटना है जिसने वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में भारत की शक्ति को स्थापित किया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और ठिकानों पर जोरदार हमला किया ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि वह किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कई शहरों और अन्य रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाने का प्रयास करके जवाबी कार्रवाई की, जिसे भारत ने प्रभावी रूप से बेअसर कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में, इसने पाकिस्तान की हवाई चेतावनी प्रणाली को नष्ट कर दिया और उसके हवाई ठिकानों पर इतनी सटीकता से बमबारी की कि पाकिस्तान दंग रह गया। युद्ध की उचित घोषणा के बिना ही युद्ध विराम कर दिया गया, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत किसी भी रक्षा कवच को भेद सकता है और असाधारण सटीकता के साथ और नागरिकों और गैर-सैन्य संपत्तियों को शून्य संपार्श्विक क्षति के साथ लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसने भारतीय हथियारों और उन्हें संभालने वाले लोगों की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। इसने यह भी दर्शाया कि भारतीय सशस्त्र बल रक्षा प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ पर समन्वित हमला कर सकते हैं। एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत के उदय ने मौजूदा शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया है।

अमेरिका अब निर्विवाद महाशक्ति नहीं रहा। चीन को अभी भी एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना बाकी है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है और यूएसएसआर के पुराने गौरव को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने एक से अधिक बार कहा है कि यूरोपीय देशों को खुद की रक्षा करनी चाहिए।

यह नाटो के कमजोर होने की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में सामने आने वाली कोई भी शक्ति संरचना भारत को अपने साथ शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी क्योंकि इसमें अपनी जनसांख्यिकीय ताकत, तकनीकी कौशल और सैन्य कौशल के कारण शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है। भारत सर्वांगीण सफलता की दहलीज पर है।

आप की बात

महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धि

भारतीय महिलाओं की वैज्ञानिक क्षमता ने स्वदेशी पूर्वानुमान प्रणाली में नई उपलब्धि हासिल की है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम-बीएफएस की सफलता नई तकनीकी उपलब्धि है। इस प्रणाली को पांच महिला वैज्ञानिकों की टीम ने विकसित किया है जो विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूती से रेखांकित करता है। परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान माने जाने वाले विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की यह भागीदारी सामाजिक सोच में बदलाव की दिशा में प्रेरक परिवर्तन है। बीएफएस जैसी जटिल प्रणाली के विकास में महिलाओं का नेतृत्व यह साबित करता है कि निर्णयात्मक और नवाचार आधारित कार्यों में महिलाएं पूरी तरह सक्षम हैं। इन विज्ञानियों ने तीन वर्षों तक अथक परिश्रम कर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो गांव और पंचायत स्तर तक सटीक मौसम की जानकारी पहुंचा सकेगी। उनका योगदान न केवल देश की वैज्ञानिक ताकत को बढ़ाता है बल्कि आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को भी विज्ञान में करियर चुनने के लिए प्रेरित करेगा। यह महिला सशक्तिकरण और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का सशक्त संगम है। प्राथमिक स्कूलों से ही बच्चियों को इन उपलब्धियों की जानकारी देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- अमृतलाल मारू, इंदौर

आपरेशन सिंदूर के परिणाम

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य दक्षता और रणनीतिक संकल्प को स्पष्ट रूप से विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध इस सुनियोजित कार्रवाई ने न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश दियाए बल्कि विश्व शक्तियों को भी भारत की क्षमताओं से अवगत करा दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वे इस बार भारत को संयम की पुरानी नसीहतें देने के बजाय वे उसकी आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार कर रहे थे। यह भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है। यदि यह अभियान कुछ दिन और चलता तो भारत की सैन्य श्रेष्ठता और भी मुखर होकर सामने आती। इससे दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक समीकरण बदल सकते थे जो स्वाभाविक रूप से कुछ महाशक्तियों को असहज करता। वे नहीं चाहते कि भारत केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति के रूप में भी उभरे। अब भारत को अपनी सैन्य सफलता को रणनीतिक बढ़त में बदलने के साथ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूती से स्थापित करना है। भारत के सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि यह भावना स्थाई रूप से बनी रहेगी।

- मधु सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

बाल गीतों का जादू

बाल गीतों का जादू लंबे समय तक छाया रहा है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बच्चे मन के सच्चे, माँ तू कितनी सुंदर है, लकड़ी की काठी जैसे गीत आज भी बच्चों के साथ-साथ बड़ों के मन को भी भावविभोर कर देते हैं। इन गीतों में सरलता, मधुरता और भावनाओं की गहराई होती थी। संगीत संयोजन ऐसा होता था कि वह पीढ़ियों तक याद रहता। अब बच्चों के लिए खासतौर से लक्षित वैसी रचनात्मकता और सादगी कम दिखाई देती है। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण है संगीत का व्यवसायीकरण। अब गानों का उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि अधिकतम कमाई बन गया है। गायन और लेखन में परिश्रम, अभ्यास और शास्त्रीय संगीत का अध्ययन अब प्राथमिकता नहीं रही। शायद इसका कारण यह भी है कि अब जीवन उतना सरल और सहज नहीं रहा तथा आम जनजीवन से अलगाव घातक रूप से सबको प्रभावित कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों का बचपन और उसकी सुंदरता वापस लौटाई जाए जो उनकी देखभाल और प्राथमिक शिक्षा में बाजारीकरण से नष्ट हुई है। ऐसी स्थितियां पैदा होने पर शायद फिर से पहले की तरह बाल गीत लिखे जाने लगें और उनका जादू हमें आनन्दित करता रहे।

- विभूति बुपक्या, खाचरौद

जानवरों से संकट

देश भर में आवारा कुत्तों के बच्चों एवं बुजुर्गों को काटने की घटना रोज सुनने एवं देखने को मिलते हैं लेकिन देश की राजधानी से लेकर अन्य शहरों में भी बंदरों का आतंक भी कम नहीं है। हापुड़ में बंदर के आतंक के कारण एक स्कूल छात्रा मृत्यु का शिकार हो गई जो छत पर पढ़ रही थी। बंदरों के डर से उसे छत से नीचे कूदना पड़ा था जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी प्रकार शहरों में आवारा जानवर और गोवंश भी बाजारों में घूमते नजर आते हैं। यह जानवर कभी भी हिंसक हो जाते है और लोगों की दर्दनाक मृत्यु का शिकार होना पड़ा है। हालांकि, राज्य सरकारें आवारा पशुओं, बंदरों एवं कुत्तों से लोगों को बचाने के प्रयास करती हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल होते नहीं दिखते हैं। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में आवारा जानवरों की संख्या बहुत बड़ी है। भारत में कुत्तों, बंदरों और गोवंशों को भोजन-पानी देने की परंपरा रही है जिससे इनकी संख्या बढ़ी है क्योंकि शहरों में इनको आसानी से भोजन-पानी मिल जाता है। आवारा जानवरों से लोगों को बचाने के लिए जन-सहयोग से व्यापक योजनायें बननी चाहिए।

-वीरेंद्र कुमार जादव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

हां 90% नहीं 10% — क्या दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है?

हां 75% नहीं 25% — क्या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ कर विश्व की चौथी सबसे ड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ी अर्थव्यवस्था न सिर्फ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराती है बल्कि वैश्विक स्तर र भी एक देश को एक आर्थिक शक्ति के तौर र स्थापित करती है। दुनिया हमारी बात अधिक ंभीरता से सुनती है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही हम सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देश बन सकते हैं। सभी देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ बेहतर व्यापारिक और द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। चौथी ड़ी अर्थव्यवस्था की राह में आगे बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज भी हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 2,500 डालर है, जो हमें कम आय वाले देशों के बीच में रखती है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना विकसित भारत की राह में एक अहम पड़ाव भर है, इस उपलब्धि के मायने और आगे की चुनौतियों की पड़ताल ही आज का अहम मुद्दा है?

चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आगे की चुनौतियां

जीडीपी क्या है?

अर्थव्यवस्था की सेहत को ट्रैक करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश में तय समय में बनाई सभी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां उत्पादन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है।

दो तरह की होती है जीडीपी

जीडीपी दो तरह की होती है। रियल जीडीपी और नामिनल जीडीपी। नामिनल जीडीपी का कैलकुलेशन मौजूदा कीमत के आधार पर किया जाता है। वहीं रियल जीडीपी में वस्तुओं और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन महंगाई दर को हटा कर किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।

कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी?

जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी=सी+जी+आइ+एनएक्स। यहां सी का मतलब है निजी खपत, जी का मतलब सरकार का खर्च, आइ का मतलब निवेश और एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट यानी कुल निर्यात है।

जीडीपी कैसे घटती बढ़ती है?

जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए चार अहम इंजन होते हैं। पहला है, आप और हम। आप जितना खर्च करते है, वह हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। दूसरा है, प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। ये जीडीपी में 32 प्रतिशत योगदान देती है। तीसरा है, सरकारी खर्च। इसका मतलब है वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। इसका जीडीपी में 11 प्रतिशत योगदान है। और चौथा है, नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल निर्यात को कुल आयात से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नकारात्मक ही पड़ता है।

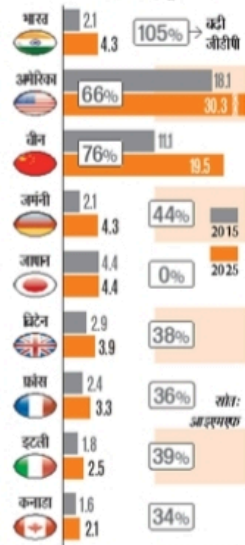

10 वर्ष में 105 प्रतिशत बढ़ी भारत की जीडीपी

आजादी के बाद ऐसे बढ़ी भारत की जीडीपी

चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से वैश्विक परिदृश्य पर असर

वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी: भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे जी20 और आइएमएफ में प्रभाव बढ़ेगा।

बढ़ेगा विदेशी निवेश: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं।

क्षेत्रीय स्थिरता: भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी, जैसे चंद्रयान-5 और सैन्य सहयोग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी।

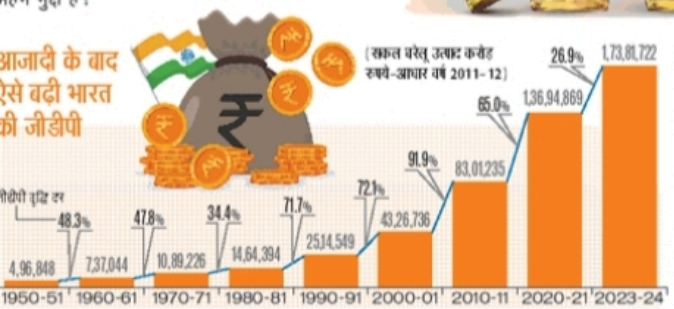

नेतृत्व: भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी।

बड़ी अर्थव्यवस्था का आज जन जीवन पर असर

रोजगार के अवसर: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होते हैं, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में।

बेहतर जीवन स्तर: बढ़ती जीडीपी और निवेश से इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होता है।

उपभोक्ता की ताकत: बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है।

चुनौतियां: आय का असमान वितरण और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं। सरकार को इनका समाधान करना होता है।

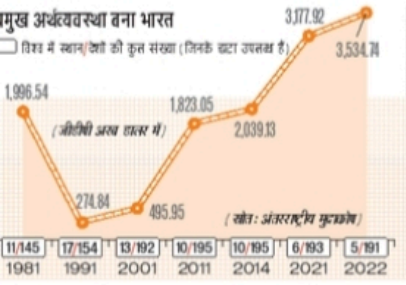

प्रमुख अर्थव्यवस्था बना भारत

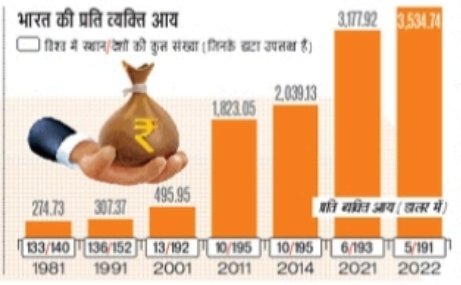

भारत की प्रति व्यक्ति आय

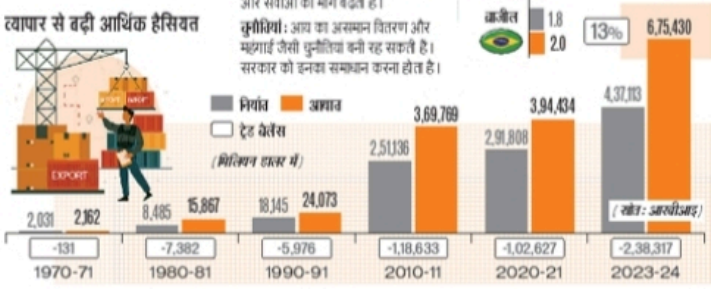

व्यापार से बढ़ी आर्थिक हैसियत

लक्षित सुधारों से ही आएगी समृद्धि

डा. विकास सिंह
विशेषज्ञ, समग्र विकास

भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। कम आय और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौतियों के बीच जरूरी है कि भारत लक्षित सुधारों को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही भारत अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से साकार कर सकता है।

हैदराबाद के टेक कारिडोर और कोलकाता के बाजारों की हलचल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक नई कहानी लिख रही है, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हालांकि, हमारी प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपये है, जो अमेरिका (75 लाख रुपये) और चीन (11 लाख रुपये) की तुलना में बहुत कम है। यह स्थिति बताती है कि समृद्धि के मोर्चे पर हम काफी पीछे हैं।

अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 2027 तक जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन चीन (लगभग 19.5 ट्रिलियन डालर) या अमेरिका की (लगभग 29 ट्रिलियन डालर) अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए कई दशकों का समावेशी विकास आवश्यक है। भारत की बढ़ती विश्वसनीयता और वैश्विक बाजारों में विश्वास, स्थायी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। चुनौती केवल विकास करना नहीं है, बल्कि सभी के साथ मिलकर विकास करना है। भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी है, और इसकी औसत आयु 28 वर्ष है। यह चीन की औसत आयु 39 वर्ष से काफी कम है। युवा जनसंख्या भारत के लिए एक सुनहरा मौका देती है लेकिन इस अवसर को भुनाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है, ताकि हर युवा भारतीय देश की प्रगति में योगदान दे सके। 2022 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 60 प्रतिशत भारतीय सालाना 4 लाख रुपये से कम कमाते हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में निवेश के बिना, यह जनसांख्यिकीय लाभ एक बोझ बन सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन आंतरिक खपत से चलता है, जो जीडीपी का 65 प्रतिशत योगदान करती है। भारत का उपभोक्ता बाजार केवल समृद्ध नहीं है, बल्कि यह विभिन्न आर्थिक स्तरों में विभाजित है। शीर्ष एक प्रतिशत की जीवनशैली बहरीन के समकक्ष है, जबकि अगले 5 प्रतिशत ब्रिटेन की समृद्धि का आनंद लेते हैं। हालांकि, आधी जनसंख्या के पास पर्याप्त खरीद शक्ति नहीं है। विकास का वितरण असमान है। शहरों में माल फल-फूल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तस्वीर इतनी गुलाबी नहीं है। भारत बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह और डिजिटल पुल अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाओं के लिहाज से शहरी क्षेत्र बेहतर स्थिति में हैं लेकिन ग्रामीण भारत को भी इस विकास में शामिल किए बिना भारत की ग्रोथ की कहानी पूरी नहीं होगी। भारत की आर्थिक प्रगति को गहरी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 करोड़ भारतीय 200 रुपये प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। करीब आधी आबादी को रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र जीडीपी में केवल 16 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत की संभावनाओं को साकार करने के लिए लक्षित सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार केवल जीडीपी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां युवा जनसंख्या, मजबूत खपत और बुनियादी ढांचे का विकास इसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहा है। लेकिन गरीबी और आय में असमानता की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत को केवल विकास नहीं करना है, बल्कि सभी के साथ मिलकर विकास करना है। तभी हम सही मायने में एक समृद्ध देश बनेंगे।

आपकी आवाज

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने का ही नतीजा है कि आज हम गरीब और वंचित तबके के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला पा रहे हैं। इससे 20 करोड़ से अधिक आबादी को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। हालांकि एक बड़ी आबादी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी लंबा सफर तय करना है।

मनोज कुशवाहा

दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत का उभरना बड़ी बात है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी प्रति व्यक्ति आय अभी भी 2500 डालर के आसपास है। यह विकसित देश तो छोड़िए चीन से भी काफी कम है। चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब 13,000 डालर है। ऐसे में अब हमें लोगों की आय बढ़ाने पर केंद्रित योजनाओं पर संसाधन खर्च करने चाहिए। इसके लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी मुहैया करानी होंगी।

गोपाल मिश्रा

बड़ी अर्थव्यवस्था बनना महत्वपूर्ण है लेकिन भारत में आय के मोर्चे पर असमानता बहुत अधिक है। देश के 10 प्रतिशत लोगों के पास पैसा है बाकी 90 प्रतिशत आबादी किसी तरह कमा कर जीवन यापन कर रही है। इस आबादी के पास जीवन चलाने के लिए जरूरी चीजें खरीदना भी आसान नहीं है। हमें सिर्फ विकास नहीं समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे विकास का फायदा सबको मिले।

प्रमोद यादव

विकसित भारत का लक्ष्य ज्यादा अहम

अनिल भारद्वाज
सेक्रेटरी जनरल, फिस्मे

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ हम जल्दी या थोड़ी देरी के साथ दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होंगे। इस बात का जश्न मनाते समय हमें यह याद रखना होगा कि प्रति व्यक्ति आय समृद्धि का पैमाना है। ऐसे में हमारे लिए विकसित भारत की रणनीति पर ज्यादा जोर देना होगा

चार ट्रिलियन डालर की जीडीपी का आंकड़ा पार करने के बाद भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। अब केवल जर्मनी, चीन और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। अगले 18-24 महीनों के भीतर, भारत जर्मनी से भी आगे निकल सकता है। आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है? हम 2047 तक विकसित देश, विकसित भारत बनने से कितने दूर हैं? पिछले 30 वर्षों से 6 प्रतिशत से अधिक की सतत आर्थिक वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाया है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हर तरफ बदलाव दिख रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण संपर्क दोनों में सड़क नेटवर्क, बंदरगाह और हवाई अड्डे, रेलवे का विद्युतीकरण, सभी के लिए बिजली और रसोई गैस तक पहुंच आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। व्यय की गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार हुआ है, जिसने विकास की गति के लिए एक अच्छा चक्र बनाया है। हालांकि, हम भारतीयों में जल्दी जश्न मनाने की प्रवृत्ति होती है। स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था के जापान से आगे निकलने की खबरें सुर्खियां बन रही थीं, उसी समय एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर एक रिपोर्ट पेश की। चीन इस सूची में सबसे आगे है, भारत और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, कई पाठकों को आश्चर्य हो सकता है कि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में इन तीनों के अलावा इंडोनेशिया चौथे, नाइजीरिया पांचवें, पाकिस्तान छठे और मिस्र सातवें स्थान पर हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था का आकार काफी हद तक जनसंख्या पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर, अधिक आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था भी बड़ी होगी। इसलिए, जब हम जापान को पीछे छोड़ने का जश्न मना रहे हैं हमें याद रखना होगा कि प्रति आय का माप वास्तविक समृद्धि निर्धारित करता है। 2047 तक विकसित देश बनने की रणनीतियों पर नीति आयोग को प्रस्तुत एक पेपर में, मैंने तर्क दिया था कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए, भारत को प्रति व्यक्ति आय लगभग 20,000 डालर के साथ 30 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि 2047 तक वार्षिक विकास को 10% से अधिक बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम 2047 तक विकसित होना चाहते हैं तो छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है पेपर में मैंने कहा था कि 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान 35 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, जिसमें विनिर्माण से 25 प्रतिशत, उसके बाद सेवाओं का 55 प्रतिशत और कृषि का 10 प्रतिशत शामिल है। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान देते हैं, लेकिन कई कारणों से वे गंभीर दिक्कतों ग्रस्त हैं। उदारीकरण के बाद बड़े कारपोरेट क्षेत्र संयुक्त उपक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से दुनिया के साथ तकनीकी अंतर को पाट रहे हैं जैसे हीरो के साथ होंडा, बजाज के साथ कावासाकी, मारुति के साथ सुजुकी। एमएसएमई अपने सूक्ष्म आकार की सीमाओं और संसाधनों की कमी के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपग्रेड और प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे हैं।

कल्पमेधा

मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा। मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा।
- बेंजामिन फ्रैंकलिन

संदेश से आगे

आतंकवाद को शह और संरक्षण देने के मसले पर पाकिस्तान की भूमिका जगजाहिर रही है। हैरानी की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार आतंकियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन उस पर कभी का असर नहीं पड़ा। उल्टे जब भी मौका मिला, पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को हर स्तर पर खाद-पानी मुहैया कराया और खासतौर पर भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम में आतंकी हमला उसकी कुत्सित मंशा की ही एक कड़ी थी, जिसमें छब्बीस लोगों की जान चली गई। वह घटना एक तरह से भारत के धीरज की हद को चुनौती देने जैसी थी, जिसके बाद भारत ने इसका संयमित, लेकिन उचित प्रतिकार किया। पाकिस्तान की सीमा के भीतर स्थित कई आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया और बहुत सारे आतंकियों को मार गिराया। इस सबके बावजूद पाकिस्तानी ठिकानों से आज भी कई कुख्यात आतंकवादी चेहरे और संगठन बिना किसी बाधा के अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

इस हकीकत के समांतर पाकिस्तान किस आधार पर भारत के साथ संवाद और इसके जरिए किसी समस्या के हल की उम्मीद कर रहा है। गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकी हमले के प्रतिकार में भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की और उसमें भारत को बड़ी कामयाबी मिली, तो उसके बाद पाकिस्तान के सामने यह लाचारी खड़ी हो गई कि वह संवाद की ओर कदम बढ़ाए। इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह भारत के सामने बार-बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। सवाल है कि एक ओर आतंक को संरक्षण और दूसरी ओर संवाद का सहारा जैसे दोहरे पैमानों के साथ पाकिस्तान किस तरह खुद को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वाभाविक ही यह दो टूक संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के लिए सचमुच गंभीर है तो पहले उसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादियों- हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को यह सलाह भी दी है कि अपने हित में वह अपनी धरती से जारी आतंकवाद को खुद ही उखाड़ फेंके।

विडंबना यह है कि वैश्विक आतंकवाद के पोषण का एक गढ़ बन चुके पाकिस्तान के बारे में संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम देश समझते हैं और समय-समय पर उसे आतंकी मकड़जाल से निकलने की सलाह देते रहे हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि अन्य देशों और खासतौर पर भारत को आतंकवाद के सहारे परेशान करने वाला पाकिस्तान कई बार खुद भी आतंकी हमलों की त्रासदी झेलता है, लेकिन आतंकियों को संरक्षण देने और बचाने से बाज क्यों नहीं आता। अफसोस की बात है कि इन आतंकियों के अलावा कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए और भाग कर दूसरे देशों में शरण लिया हुआ है। आतंकवाद के साथ-साथ अन्य आर्थिक भगोड़ों की वजह से भारत को होने वाले नुकसान की सिर्फ निंदा करने के बजाय उन्हें वापस लाना और कानून के कठघरे में खड़ा करना वक्त का तकाजा है। ऐसे में अगर देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है तो यह एक बेहतर प्रतिक्रिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब सख्त संदेश या चुनौती की भाषा में सिर्फ संवाद करने के बजाय पाकिस्तान में पनाह पाए और पल रहे कुख्यात आतंकियों को भारत लाने के लिए कार्रवाई के स्तर पर भी ठोस पहल हो।

बीमार स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत लगातार बिगड़ रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। प्रति वर्ष बजट में स्वास्थ्य के लिए जो राशि तय होती है, वह इतनी नहीं जिससे सभी नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सच्चाई यही है कि गंभीर बीमारी का इलाज कराने के क्रम में आम आदमी की सारी जमा-पूंजी खत्म हो जाती है। इसी वजह से कई परिवार तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह दुखद ही है कि आजादी के बाद से अब तक हम शहरों और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा नहीं बना पाए हैं। आज भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसका नतीजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ता है। बीते दिनों बलिया में मोबाइल फोन की रोशनी में चार महिलाओं का प्रसव कराया गया। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की एक और बानगी है। कई अस्पतालों में जेनरेटर और डीजल के अभाव का बहाना बनाया जाता है, लेकिन वहां इसकी सुविधा उपलब्ध होने पर भी यह नौबत क्यों आई, यह जांच का विषय है। इसी जिले में पिछले दिनों जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था उजागर हुई।

हकीकत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली आज भी कायम है। आबादी के लिहाज से सरकारी अस्पतालों की संख्या काफी कम है। गांवों के मरीज उपचार के लिए शहरों की तरफ भागते हैं, जहां निजी अस्पतालों में अपनी थोड़ी बहुत बचत भी गंवा बैठते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि सेहत की देखभाल पर आम आदमी का खर्च कम क्यों नहीं हो रहा? यह सरकार के लिए भी एक चुनौती है। फिलहाल इस पर जोर देने की जरूरत है कि मरीजों का सुरक्षित उपचार हो और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। बलिया की घटना से पहले भी टार्च की रोशनी में इलाज और आपरेशन किए जाने की खबरें आती रही हैं। उपचार में देरी और गलत निदान की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसला अब बुनियादी सुविधाओं का भी है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और बदहाली पर सवाल उठते हैं, तो यह गलत नहीं हैं।

विकसित भारत की राह और युवा शक्ति

प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए, तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है।

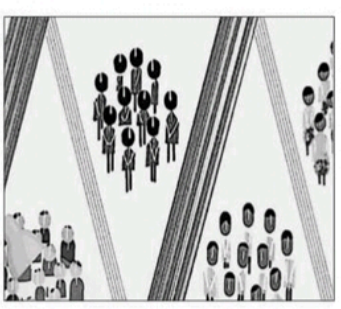

रवि शंकर

युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। युवाओं का एक समृद्धिशाली इतिहास है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवावस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था।

पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इतिहास ने युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा है। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उसमें विजय हमेशा हमारी ही होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आजादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया। कई युवाओं ने बलिदान तक दिया। परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश राज को खत्म करने में कामयाब हुआ। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाया जाए, तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए, तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पच्चीस वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का पचास फीसद हैं। जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी देश अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यही कारण है कि भारत को दुनिया भर में उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान, बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। हमारी यही युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी।

हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं। चूंकि, युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात भी सौ फीसद सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है। मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान का ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की नई इबारत लिखी और आज वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़ीशा जैसे राज्य तमाम संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल और कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे हैं। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश कर मानव संसाधन को मानव पूंजी में तब्दील कर दिया जाए, तो निश्चय ही भविष्य में इसका बेहतर प्रतिफल मिलेगा।

> युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या के विकास का संकेत भी देते हैं। चूंकि, युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। यह बात भी सौ फीसद सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है। मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं, तो क्या हम यह सोचते हैं कि वह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा! वह युवा जो रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है? वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर देश छोड़ कर चले जाने के लिए विवश हैं? या फिर वे युवा जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं, लेकिन विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है? वे साक्षर तो हैं, लेकिन शिक्षित नहीं। आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहां युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी जैसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है।

यह सच है कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल-कारखानों, कृषि, विज्ञान और तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्त्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र को मजबूती मिलती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं। जिससे वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक संपर्क और राजनीति एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ा कर समाज में उचित स्थान पा सकें। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। वह अगर चाहे तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली विसंगतियों, असमानता, अशिक्षा और अपराध आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। लेखक अर्नाल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक 'सरवाइविंग द फ्यूचर' में नौजवानों को सलाह देते हुए लिखा है, 'मरते दम तक युवावस्था के जोश को कायम रखना।'

बहरहाल, बरसों से विकास के बावजूद, युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफी चुनौतियां झेल रहे हैं। फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते-बिखरते हुए नहीं रहने देना है, बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। कुछ युवा जरूर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि समाज में व्याप्त कई समस्याओं पर कार्य कर युवा दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। युवा अपने देश का भविष्य होते हैं तथा उस देश की प्रगति और विकास में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। कोई दो मत नहीं कि हमारे युवा भी देश के विकास में महत्त्वपूर्ण अंग हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है।

विचारों की यात्रा

दुनिया मेरे आगे

एकता कानूनगो बक्षी

किसी भी काम की नींव दिमाग में उत्पन्न विचार से बननी शुरू होती है। हर नया अनूठा विचार हम सभी को विस्मित करता आया है। विचारों का मंथन जटिल प्रक्रिया है, जिसे पूरी गंभीरता से निभाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक सामान्य-सा विचार भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। जब भी हम दुनिया, समाज, स्वयं की बेहतरी, समृद्धि की बातें करते हैं या किसी और महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी अपने ही विचारों में उलझ से जाते हैं। ऐसी बातें भी कहने लगते हैं, जिनका हमारे उद्देश्य की सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। संभवतः इसका कारण मनुष्य का जटिल मन है जो कई सारी चीजों से लगातार प्रभावित होता रहता है।

जब हम किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं, निर्णायक भूमिका में होते हैं या हमारे विचारों से दूसरों या स्वयं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, तो हमें अपने मन को संतुलित करना, उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक सोच के साथ हमें अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। उद्वेलित मन कभी भी सार्थक सुझाव नहीं दे सकता है। अगर हमारे विचार हम पर हावी होने लगें और हम अपने भीतर का संतुलन खोता हुआ महसूस करें, तो हमें खुद को शांत कर लेना चाहिए।

अक्सर अशांत और कुंठित मन के साथ हम आशावाद का चोगा पहनकर प्रयास जरूर कर रहे होते हैं कि भविष्य से जुड़ी उम्मीदों की बातें की जाएं, समाधान खोजे जाएं, पर हमारे भीतर का भय, भावनात्मक संताप हमें संतुलित नहीं रहने देता। हम अपने उलझनों से भरे मन से कभी स्थितियों, परिस्थितियों की निंदा करने लगते हैं तो कभी स्वार्थ और कुंठा के वशीभूत होकर वास्तविक मुद्दे को किसी और ही दिशा में ले जा रहे होते हैं। समाधान पर चिंतन करने की जगह हम दूसरों पर दोषारोपण कर खुद को विमुख कर लेते हैं। अपने विचारों की गाड़ी पर सवार होकर कभी भूतकाल और कभी भविष्य में स्वयं को और अपने अनुयायियों को घुमा रहे होते हैं। ऐसा अगर हमारे द्वारा हो रहा हो तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह रवैया हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने में असमर्थ है। हमारी यह असंतुलित, अस्पष्ट मानसिकता हमें पहले से भी अधिक पीछे की ओर धकेल देती है। उलझनों के जंजाल में हम खुद को और उलझाते जाते हैं, जबकि अगर हम खुली सोच के साथ, संतुलित और स्वस्थ मानसिक स्थिति लिए आगे बढ़ें तो निश्चित ही ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जो इतना पेचीदा हो कि वह केवल विचार-विमर्श, बहस-मुबाहिसे में ही बना रहे और कभी उसे ठोस जमीन ही न मिल सके।

विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित बनाए रखना, मुद्दे से हटकर किसी भी तरह के विचार जो केवल भटकाव के रूप में हमारे मन मे प्रवेश कर रहे हो, उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक सही शुरुआत कही जा सकती है। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें तो हमें अभी तक हमारे साथ जो भी अवांछित हुआ है, जिन लोगों ने हमें निराश किया है, हमारे जीवन के जो अभाव रहे हैं, इन भटकाव भरे विचारों में डूबकर दुखी होने में समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। अपने आप को सभी उलझनों से आजाद कर अपने विचारों और प्रयासों को आगे की सफलता की रणनीति बनाने पर केंद्रित कर देना चाहिए।

> जब हम अपनी दुनिया, अपने समाज को लेकर सपना देखते हैं, जिसमें हम सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर रहे होते हैं, तब हम मनुष्य को हटाकर परियोजना नहीं बना सकते हैं। समाज मनुष्य से बनता है। हमारे प्रयास मनुष्य को सशक्त बनाने के लिए होने चाहिए।

इसी तरह, जब हम अपनी दुनिया, अपने समाज को लेकर सपना देखते हैं, जिसमें हम सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर रहे होते हैं, तब हम मनुष्य को हटाकर परियोजना नहीं बना सकते हैं। समाज मनुष्य से बनता है। हमारे प्रयास मनुष्य को सशक्त बनाने के लिए होने चाहिए। मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के साथ ही, इस पर भी चिंतन किया जाना चाहिए कि उसे कैसा परिवेश मिल रहा है, सम्मान, स्नेह, आत्मीयता से हर इंसान के भीतर के अच्छे गुणों को उभरने के लिए जमीन मिलती है। अच्छी सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर जीवन स्तर गरिमामय, जीवन बिताने में सहायक बनता है। वहीं उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के अच्छे अवसर मुहैया करवाना- यह इंसान के जीवन को खुशियों और संतुष्टि के भाव से भर देते हैं।

सुंदर समाज बनाने के विचार के केंद्र में इंसान के उत्थान के मुद्दे से इतर किसी और मुद्दे पर बात करते समय यह समझना चाहिए कि कहीं यह किसी तरह का वैचारिक भटकाव तो नहीं है। हमारे विचार हमारी ही जीवन यात्रा और अनुभवों का परिणाम होते हैं, जिनका बार-बार हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। नकारात्मक अनुभवों के बाद भी हम संतुलित, स्वस्थ, निष्पक्ष सोच बनाए रख सकते हैं। हमें अपने मन में उत्पन्न हो रहे अनावश्यक भटकावों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए।

विचारों के मंथन में ढेर सारे विचारों के बीच कुछ ही विचार ऐसे होते हैं, जिनकी हमेशा मिसाल दी जाती है, वे हमेशा सबके लिए पथ-प्रदर्शक बन जाते हैं और हर समय प्रासंगिक बने रहते हैं। ये विचार गहरे चिंतन, मनन, दूरदर्शिता, एकाग्रता, उदारता, परिपक्वता, अध्ययन , ठहराव और बिना पूर्वाग्रह सीखने-समझने की इच्छाशक्ति से उत्पन्न होते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने विचारों को हमेशा संतुलित, स्वस्थ और परिष्कृत करते रहें।

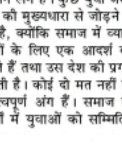

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

धुएं में फिक्र

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को पूरे विश्व में मनाया गया। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे लोगों को बताने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा संस्थानों में भी इस पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। मगर तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब लोग तंबाकू से स्वयं दूर होंगे। दुनियाभर में तंबाकू हर साल लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। दरअसल, नशा कोई भी हो, वह इंसान को मौत के मुंह तक ले ही जाता है। विभिन्न तरह का नशा कई लोगों की जिंदगी निगल चुका है। इससे कई घर बर्बाद हो चुके है। लेकिन यह सब जानते हुए भी पता नहीं क्यों लोग नशे के आदी हो रहे हैं! दरअसल, नशा कोई भी हो, हमेशा बर्बादी ही करता है। तंबाकू का नशा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके साथ ही यह दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक सिद्ध होता है। तंबाकू सेवन करने वाला जब थूकता है, तो वह दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ा देता है।

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

सराहनीय पहल

शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो, जब देश के किसी हिस्से में सड़क दुर्घटना नहीं हुई हो। दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने का निर्णय निश्चित ही वरदान साबित होगा। इस योजना से नागरिकों में सहायता करने का जज्बा भी आएगा। पहले सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले व्यक्ति भी बेवजह पुलिस कार्यवाही, अनावश्यक पूछताछ और अन्य परेशानियों के कारण मदद करने के बजाय मूकदर्शक बने रहते थे। मध्यप्रदेश में शुरू की गई 'राहवीर योजना' के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना से अब लाखों घायलों की जान बचाई जा सकती हैं। जिला स्तर से केंद्र सरकार तक राहवीर सम्मानित होते रहेंगे। घायलों को जिंदगी देने में यह योजना मददगार साबित होगी। साथ ही लोगों में सेवा भाव के साथ जागरूकता आएगी। नागरिकों को प्रोत्साहित करने की यह पहल वास्तव में सराहनीय है। इस तरह की योजना पूरे देश में लागू की जानी चाहिए।

- योगेश जोशी, बड़वाह

हारते लोग

पंचकूला में सात लोगों की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वे लोग जिंदगी से हार मान चुके थे? क्या उनके पास कोई अपना नहीं था, जिससे अपना दुख साझा कर सकते या आर्थिक मदद मांग पाते? आत्महत्या के अलावा क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? क्यों लोग अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारते हैं? स्कूल शिक्षकों का कहना है कि कुछ दिन पहले माता-पिता जब पीटीएम में आए थे, तो दोनों सामान्य थे। क्या इंसान अपने दर्द को दबा कर दुनिया के सामने दिखावा कर रहा होता है? क्या समस्याएं इंसानियत से ज्यादा बड़ी हो गई हैं आजकल कि मिल-बांट कर सुलझाई नहीं जा सकतीं। ऐसे कई सवाल दिल को चुभते हैं। आज के परिवेश में जरूरत है एक दूसरे को समझने की, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और मिल-जुल कर समस्याओं का समाधान निकालने की। जिंदगी से हार मान लेना कोई समझदारी नहीं। खुदकुशी एक तरह से जिंदगी से पलायन है।

- अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

समर्थन के समांतर

'बेहतरी की फसल' (संपादकीय, 29 मई) पढ़ा। वर्ष 2025 की खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ा दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि घोषित दर पर खरीदी करेगा कौन? पिछले दो साल से सोयाबीन घोषित समर्थन मूल्य से एक हजार से लेकर डेढ़ हजार कम दाम पर बिक रहा है। दूसरी फसलों के भी मंडी में समर्थन मूल्य से कम दाम किसानों को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित दामों का क्या औचित्य रह जाता है? सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए समय-समय पर कई निर्णय लेती रही है, लेकिन किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में ये निर्णय नाकाफी साबित हुए हैं। जब तक किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, तब तक ऋण से उन्हें मुक्ति मिलना असंभव है। सरकार द्वारा समय-समय पर समर्थन मूल्य निर्धारण मात्र औपचारिकता भर रह जाता है।

- हुकुम सिंह पंवार, इंदौर

अत्यधिक बारिश

असम सहित पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में तेज बारिश से 25 से ज्यादा लोगों की मौत दुखद और चिंताजनक है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पहले से ही बाढ़ की स्थिति थी और रविवार की भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त करके रख दिया। ब्रह्मपुत्र सहित असम की 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सवाल है कि अत्यधिक बारिश के क्या कारण हैं? इधर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में तीन-चार बार भारी बारिश, आंधी, अंधड़, बिजली चमकना और खूब गड़गड़ाहट देखी गई है। बारिश का यह ढंग सामान्य नहीं है, ऐसा लगता है, मानो कोई भारी विपत्ति टूट पड़ी हो। कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए शोधपत्र से पता चलता है कि देश भर में प्रतिदिन होने वाली अतिशय या अत्यधिक वर्षा लगातार बढ़ रही है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। नेचर पत्रिका में भी समय-समय पर इस विषय पर शोध प्रकाशित होते हैं, जिनमें चिंता का इजहार होता है।

एक शोध में मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने 1969 से 2010 के बीच दर्ज की गई बारिश के आंकड़ों का अध्ययन किया है और उन्हें साल-दर-साल भारी या अतिशय बारिश का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। अतिशय बारिश को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है, पर आंकड़ों के सहारे ज्यादा गहरे अध्ययन की जरूरत है। मौसम विज्ञान विभाग भारी बारिश संबंधी अनुमान तो लगा लेता है, पर किस इलाके में भारी बारिश की वजह से प्राकृतिक आपदा आएगी, यह बताना कठिन है। साल 2022 के वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि असम व मेघालय के ज्यादातर जिलों में 48 लाख से अधिक लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। कुल 43 जिलों में से 79 प्रतिशत प्रभावित हुए। यह समझना चाहिए कि वर्षा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। भारी वर्षा का मतलब एक दिन में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी बारिश, बहुत भारी वर्षा का मतलब- एक दिन में 115.6 मिमी से 204.5 मिमी और अत्यधिक भारी वर्षा का मतलब - एक दिन में 204.6 मिमी या उससे अधिक बारिश। अत्यधिक बारिश का मतलब है कि सारी चीजों को बहा ले जाने को बेताब बारिश। इसमें सबक यही है कि लोग केवल मजबूत जगहों पर ही अपना घर बनाएं और घरों की मजबूती का निरंतर ध्यान रखें।

साल-दर-साल कम समय में ही भारी या अतिशय बारिश का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। अभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी यही खतरा देखा गया है।

अत्यधिक बारिश के साथ ही एक बड़ी चिंता आकाशीय बिजली को लेकर भी है, ये घटनाएं लगभग पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। इस साल की ही अगर बात करें, तो भारत में मार्च-अप्रैल महीने में आकाशीय बिजली की घटनाओं की वजह से मरने वालों की संख्या में 184 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। साल 2021-22 में हुए एक अध्ययन में पाया गया था कि बिजली गिरने से मरने वालों में 94 प्रतिशत ग्रामीण ही होते हैं। पहले खेतों में किनारे पेड़ हुआ करते थे, जो आकाशीय बिजली की स्थिति में कवच का काम करते थे और खेत में काम करने वालों पर आंच नहीं आती थी, पर अब खेतों में पेड़ों की संख्या कम हुई है। ताड़ के पेड़ों को फिजूल समझकर काटा गया है, यह काम ओडिशा और बिहार में खूब हुआ है। बिहार में ताड़ के पेड़ों को बचाने को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है, पर पिछले साल ओडिशा सरकार ने अपने स्तर पर ही राज्य में 20 लाख से ज्यादा ताड़ के पेड़ लगाने का फैसला लिया था। मतलब, चरम मौसम से जुड़ी घटनाओं या आपदाओं के समय सुरक्षित रहने के लिए हमें ऐसे अनेक छोटे-छोटे उपायों पर गौर करना होगा, ताकि हम अपने आसपास सुरक्षा घेरे को चाक-चौबंद रख सकें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 02 जून, 1950

कण्ट्रोल की अन्धेरगर्दी

कण्ट्रोल अथवा नियंत्रण वस्तुतः लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ही शुरू किये गये थे। युद्धजनित आवश्यकताओं के कारण सर्वसामान्य के उपयोग के लिए आवश्यक पदार्थों की जब कमी पड़ने लगी, तो यह स्वाभाविक था कि सुविधा-प्राप्त अथवा सम्पन्न वर्ग के अलावा भारी संख्या में सुविधाहीन अथवा असम्पन्न जो वर्ग है, उसको ये चीजें उपलब्ध न होतीं, अथवा होतीं भी, तो बहुत कम परिमाण और ऐसे मूल्य में, जो उसकी सामर्थ्य से मेल न खाता। अभाव की स्थिति से लाभ उठाने के स्वार्थ के कारण असम्पन्न वर्गों के लिए यह स्थिति विनाशक होती। इसीलिए, असम्पन्नों को अभाव और महंगाई से बचाने के उद्देश्य से, मूल्य-नियंत्रण (कण्ट्रोल) और खुराकबन्दी (राशन) को अपनाया गया। प्रयोजन यह था कि चीज यदि कम है, तो उसका ऐसा वितरण किया जाये, जिससे सुविधाहीनता के कारण कोई वर्ग उससे वंचित न रहे। इसमें बंधन होते हुए भी अच्छाई यह थी कि जीवन के लिए आवश्यक चीजें एक हद तक उचित मूल्य में हर एक को पहुंचने का आश्वासन था।

नियंत्रणों की इस उपादेयता को स्वीकार करते हुए भी यह मानना होगा कि जिनके हाथ में उनका संचालन रहा, वे उतने ऊंचे साबित नहीं हुए जितने कि उन्हें होना चाहिए था। फलतः नियंत्रणों में अनियमितता, अव्यवस्था, बल्कि भ्रष्टाचार के भी आरोप सामने आते रहे हैं। अभाव की स्थिति से स्वार्थ-साधन करने वाले वर्ग का तो इसमें रुकावट डालने वाले इस उपाय (नियंत्रण) से नाराज होना स्वाभाविक ही है, परन्तु जब सर्वसामान्य भी नियंत्रणों को बुरा कहते और उनसे असुविधा होना बताते हैं, तो मानना चाहिए कि नियंत्रणों की व्यवस्था में ही कहीं कोई खराबी या अन्धेरगर्दी है। बुधवार 31 मई को दिल्ली की हिन्दुस्तानी मर्केण्टाइल एसोसियेशन यानी कपड़े के भारतीय व्यापारियों की ओर से भारत-सरकार के नये उद्योग मंत्री श्री हरेकृष्ण महताब का स्वागत-समारोह आयोजित किया गया, उसमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। स्वागत समारोह की औपचारिक विधि के साथ-साथ व्यापारियों ने काम की यह बात भी कर डाली कि वस्त्र-नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत रखे जाने वाले विभिन्न मिलों के कपड़े के दामों की असमानता बताने के लिए कीमत लगे विविध कपड़ों का छोटा सा प्रदर्शन कर दिया। उद्योग मंत्री इससे खिन्न नहीं हुए।

गाजा के पास सिर्फ गांधी का रास्ता

गाजा में भूख से तड़पते लोगों की हालत पर संयुक्त राष्ट्र में उसके दूत को फूट-फूटकर रोते हुए गुहार लगानी पड़े, तो प्रश्न उठता है, क्या यह दुनिया दूसरों का दर्द महसूस करती है?

सुरेंद्र कुमार | पूर्व राजनयिक

लोग आज इंटरनेट, एक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, वाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिये चौबीसों घंटे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें भौगोलिक सीमाएं या जातिगत, धार्मिक व भाषायी भेदभाव कतई आड़ नहीं आते। माना यही जाता है कि इससे दुनिया करीब आ गई है! मगर क्या वाकई हम पहले की तुलना में भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के नजदीक आए हैं? क्या हम दूसरों का दर्द ज्यादा महसूस करने लगे हैं? क्या उनकी पीड़ा से द्रवित होते हैं? अगर ऐसा नहीं है, तो क्या हम सचमुच आपस में जुड़े हुए हैं? मुझे महात्मा गांधी के प्रिय गुजराती कवि नरसिंह मेहता की यह पंक्ति याद आ रही है, जो प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति की भावना को जाहिर करती है- *वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराची जाणे रे...।*

हम टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें लगातार देखते आ रहे हैं- गाजा में इजरायली सेना बमबारी कर रही है; फलस्तीनी शवों को उठाने के लिए दौड़ रहे हैं, जमींदोज इमारतों के मलबे से लाशें निकाल रहे हैं, उनको सफेद चादरों से ढक रहे हैं, ताबूत में डाल उनको कब्रों में दफना रहे हैं और आसमान की ओर हाथ उठाकर अपने रब से इस मुसीबत के फौरन खत्म होने की दुआ मांग रहे हैं। मगर उनकी दुआओं का असर नहीं हो रहा और मलबे से कब्र तक का सफर मुसलसल जारी है! जिंदा बच गए मां-बाप और बीवियों की चीख-पुकारें दर्शकों को नहीं झकझोर पातीं, सभ्य दुनिया के नेताओं को तो बिल्कुल भी नहीं!

जब भी यहां राहत और खाद्य सामग्रियों से भरे ट्रक आते हैं, तमाम मर्द-औरतों और बच्चों की बदहवास भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। अपने-अपने खाली कटोरे में एक-दो रोटी या मुट्ठी भर अनाज पाने के लिए वे एक-दूसरे से जूझते हैं। जब हफ्तों तक इन ट्रकों को यहां आने से रोक दिया जाता है, तो खाली कटोरे लिए हाथ बेबसी में शिथिल पड़ने लगते हैं। कई लोग अपनी दयनीय नियति को प्राप्त करते हैं और लगातार भूख से लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दे रहे हैं। डेढ़ साल से इन दृश्यों को देखते-देखते हम चेतना-शून्य हो गए हैं। हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। हमारी आत्मा हमें नहीं झकझोरती। हम बस टीवी चैनल बदल देते हैं।

महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर अहिंसा की महत्ता समझाई, आखिरकार अपने ही देशवासी की गोलियों के शिकार हुए थे। उनकी हत्या के बाद भी अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके संदेशों ने अमेरिका में डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर व दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत का अंत सुनिश्चित किया, जबकि तब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। गांधीजी का जीवन और उनके दर्शन ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को गति दी और दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों के रंगभेद शासन को खत्म करने में मदद पहुंचाई।

गांधीजी ने अपने जीवन में दो सिद्धांतों पर खासा जोर दिया था- महान लक्ष्य महान साधनों से ही प्राप्त किए जाने चाहिए! और, यदि आपकी आंखों के सामने हिंसा हो रही है और आपके पास विरोध करने की क्षमता व प्रतिरोध के साधन हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप भी उस हिंसा के लिए उतने ही दोषी हैं, जितना हिंसा करने वाला।

हमास द्वारा 7 अक्तूबर, 2023 को इजरायल पर किया गया हमला और बेकसूर इजरायलियों को मारना व बंधक बनाकर ले जाना निस्संदेह एक बर्बर आतंकी हमला था, जो निंदनीय और अक्षम्य था। इसके दोषियों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने और बंधकों को छुड़ाने की मंशा समझ में आती है, मगर हमास को सजा देने के लिए पूरी गाजा-पट्टी को बंजर बनाने, मीलों-मील उसे मलबे के ढेर में तब्दील करने और एक अंतहीन कब्रिस्तान में बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती! क्या 54,000 फलस्तीनियों की हत्या को जायज ठहराया जा सकता है, जिनमें 20,000 से अधिक बच्चे भी हैं? हमास ने जो किया, वह गलत था। मगर इजरायल जो कर रहा है, वह उससे हजारों गुना बड़ी गलती है। यह किसी नरसंहार से कम नहीं। क्या जान-बूझकर हजारों नागरिकों को भूखा रखना सबसे घिनौना मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है?

मगर दुनिया भर के नेता फलस्तीन मसले पर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जबकि वे मानवाधिकारों की रक्षा, राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले का विरोध करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते रहते हैं। इजरायल जो कुछ कर रहा है, उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। उन्होंने जैसे खुद को असहाय तमाशबीन बना रखा है। अमेरिका द्वारा इजरायल को राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य समर्थन के साथ जो चाहे कर सकने की छूट देना कोई रहस्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की नजरों में इजरायल कुछ गलत नहीं कर सकता। फलस्तीनियों की जान तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। असल में, फलस्तीनी अमेरिका के चुनाव नतीजों को उस तरह नहीं बदल सकते, जिस तरह से इजरायल की लॉबी कर सकती है।

अरब नेता भी ढेर सारी सहानुभूति दिखाते हैं और फलस्तीनियों की हिमायत में तमाम बयान भी जारी करते हैं, लेकिन वे असहाय गाजावासियों पर हमले रुकवाने के लिए एकजुट होकर अमेरिका पर दबाव नहीं डालते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी की हालिया यात्रा के दौरान एक देश के नेता ने लैवेंडर रंग का कालीन बिछवाया, तो दूसरे ने एक विमान भेंट की। उन्होंने 600 अरब डॉलर के निवेश का समझौता भी किया। मगर गाजा में फलस्तीनियों पर बमबारी रोकने और लंबे समय से अटके दो देश के सिद्धांत को लागू करने की समयबद्ध कार्ययोजना की सामूहिक मांग करने में वे विफल रहे।

कटु सच्चाई यही है, फलस्तीनी हथियारों से कभी इजरायल को नहीं हरा सकते। अमेरिका और प्रमुख पश्चिमी देश, यहां तक कि अरब व खाड़ी के नेता भी उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए, गांधी के मार्ग पर चलते हुए क्यों न सभी फलस्तीनी पुरुष, महिला व बच्चे गाजा और पश्चिमी तट से पूरी तरह निहत्थे होकर बाहर निकलें और इजरायलियों से कहें कि वे उनको मार दें। इजरायली बमबारी में टुकड़े-टुकड़े होने की तुलना में अपनी भूमि और अधिकारों के लिए गांधीवादी तरीके से शहीद होना उनके लिए कहीं अधिक सम्मानजनक होगा। मगर इस साहसी मार्ग पर चलने से पहले हमास को बिना शर्त तमाम बंधकों को छोड़ देना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नीलगायों को मार डालने का उपाय कितना मुनासिब

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

दो राज्यों में फैले बुंदेलखंड संभाग में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, मगर उन पर चलना जानलेवा होता जा रहा है। वजह? दरअसल, आए दिन इन सड़कों पर तेज गति से चल रहे वाहनों से एशिया की सबसे बड़ी हिरण प्रजाति रोजड़ या रोजा (नीलगाय, घोड़परास) का सामना हो जाता है। इसके कारण कई चालकों व दूसरे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

मालवा के मंदसौर-नीमच में अफीम के कई किसान इस पशु के डर से खेती छोड़ चुके हैं। इस बलिष्ठ पशु का बड़ा झुंड जब किसी खेत में घुसता है, तो फिर वहां केवल तबाही के निशान बचते हैं। इनको न किसी लाठी का डर होता है और न ही ये इंसान पर हमला करने से डरते हैं। हाल ही में बिहार में लगभग 4,000 घोड़परास या नीलगाय को मारने के लिए 600 निशानेबाजों को काम सौंपा गया है। समस्तीपुर से लेकर सारण, वैशाली और नालंदा तक आम लोगों की अर्जियां आई हैं कि नीलगाय के आतंक से मुक्ति के लिए उनको इसे मारने की अनुमति दी जाए। पिछले वर्ष बिहार में आधिकारिक रूप से 4,279 नीलगायों को मारा गया था, जिनमें सर्वाधिक उस वैशाली जिले में मारे गए, जहां अहिंसा के पुजारी गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश हुआ था।

नीलगाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भले ही राज्यों में इनके नाम अलग-अलग हों, पर सभी जगह इनका आतंक एक जैसा है।

गिर फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण (2020-21) के अनुसार, गुजरात में नीलगाय की आबादी पिछले 10 वर्षों में काफी बढ़ गई है। साल 2011 में यह 1,19,546 थी, जो बढ़कर अब 2,51,378 हो गई है। गौर करें, अमरेली में एशियाई गिर शेर का सबसे बड़ा कुनबा है और नीलगाय जैसे वन पशु उनका आहार होते हैं। इसके बावजूद उनकी संख्या बढ़ने की मूल वजह इनकी तेज प्रजनन-दर और गिर के शेरों का इस ताकतवर जीव से उलझने से बचने का स्वभाव है। उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि विभाग के अनुसार, पूरे प्रदेश में लगभग 2.33 लाख नीलगाय हैं। ललितपुर, इटावा में इनका प्रकोप ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक में भी नीलगाय की आबादी पाई जाती है और कई जगहों पर यह काफी अधिक है। भले ही राज्यों में इनके नाम अलग-अलग हों, पर सभी जगह इनका आतंक एक जैसा है।

नीलगाय के लगातार हमलों से किसान बहुत परेशान और निराश हैं। इनकी वजह से कई ने किसानी छोड़ दी है, तो कुछ मामलों में भारी नुकसान से निराश किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। नीलगायों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को लगातार रात-दिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, जो बेहद थका देने वाला काम है और बाड़ लगाने जैसे उपाय इतने खर्चीले हैं कि छोटे किसान यह कदम उठा नहीं सकते। हालांकि, कुछ राज्यों में नीलगाय को मारने की अनुमति दी गई है, मगर यह एक संवेदनशील मुद्दा है। कई लोग इसके नाम से 'गाय' शब्द जुड़ा होने के कारण इसे मारना पसंद नहीं करते।

तो क्या नीलगायों को मार डालना ही इनसे मुक्ति का एकमात्र निदान है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में किरण रानी व भूपिंदर कौर बब्बर का एक शोध कार्य पिछले वर्ष प्रकाश में आया था- *मिटीगेटिंग ब्लू बुल मेनान्स : एसेसिंग स्ट्रेटजीस फॉर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर।* इसमें नीलगायों से खेती को निरापद रखने के कई विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें एक यह भी है कि फसलों के चयन में यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, तो इस जंगली जीव को खेतों से दूर रखा जा सकता है, यानी ऐसी फसलें चुनें, जिन्हें नीलगायों द्वारा खाने की संभावना कम हो। बहरहाल, दो बातें विचार के योग्य हैं। आखिर यह शाकाहारी जानवर बस्ती की तरफ क्यों आ रहा है? दूसरी, जब पूरे देश में शेर वर्ग के जानवर बढ़ रहे हैं, तब नीलगाय उनका आहार क्यों नहीं बन रहे? क्या जंगल के जानवरों के आहार की प्रकृति बदल रही है?

हो सकता है नीलगायों को मारना इस समस्या का फौरी हल हो, पर इतने बड़े जीव को यूं बड़ी संख्या में मार देना नैसर्गिक न्याय व जीवन-चक्र के विपरीत है। इसके लिए वन्य प्रबंधन को इनके वजन व झुंड को बढ़ने से रोकना चाहिए। इनकी पसंदीदा वनस्पति जंगलों में अधिक उगाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कांटों का भी वजूद मानें

अभी-अभी एक खूबसूरत शेर पढ़ी- *गुलशन-परस्त हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं।* यानी, मैं फूलों के बाग का प्रेमी हूं, लेकिन मुझे फूल ही प्यारे नहीं लगते, मैं कांटों से भी मोहब्बत करता हूं।

यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस फलसफे को वास्तविक जीवन में उतारना आसान नहीं है। मन कल्पनाशील है, इसलिए सुंदर सतरंगी कल्पनाएं बनाकर लुभाता रहता है, मगर इसका अनुभव करना हो, तो कल्पना के आसमान से उतरकर सच के धरातल पर आना पड़ता है। कांटे, यानी जो भी दुखद है, जो भी नकारात्मक है, उसका स्वीकार। उसके प्रति तो हमें तिरस्कार ही सिखाया गया है, उसे हम अपने भीतर कहीं गहरे दबा देते हैं। जीवन को अच्छे और बुरे में बांटकर हमने खुद के साथ बड़ा अन्याय किया है। यह न केवल गलत है, बल्कि असंभव भी है।

जिंदगी आदमी के रूमानी ख्यालों से नहीं चलती, उसके अपने नियम हैं, जो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। हमारा पूरा अस्तित्व बना है तरंगों से; यह ऊर्जा का महासागर है और ऊर्जाएं स्वभावतः एक-दूसरे के विपरीत और परिपूरक होती हैं। जो विपरीत दिखाई देता है, वह दूसरे को सहारा देता होता है। मजे की बात है, दो विपरीत एक-दूसरे को सम्हालते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि सच में आपके जीवन का फूल खिले, तो कांटों से दूर रहने की आदत छोड़ दें। ज्योति अंधेरे में ही जगमगाती है। पत्थर पर जब छेनी चलती है, तभी तो मूर्तियां निर्मित होती हैं। अगर पत्थर कह दे कि नहीं, छेनी मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे काटो मत। मैं जैसा हूं, मुझे वैसा ही रहने दो; तो वह अनगढ़ ही रह जाएगा। छेनी की चोट सहना उसके लिए जरूरी है। लोग कांटों से इसलिए बचते हैं कि उनके छिदने पर जो दुख होता है, जो खून बहता है, उसकी पीड़ा सहने की उनमें ताकत नहीं होती। कांटों से निबाह करना काफी नहीं है, कांटों से भी उतना ही प्रेम करना होगा, जितना फूलों से। अगर आपने कांटों से प्रेम न किया, तो आप प्लास्टिक के फूल ही खरीद लाएंगे, क्योंकि उन्हीं में कांटे नहीं होते।

जिंदगी के दोहरे चरित्र को भली-भांति पहचानिए। अगर आपने जिद की कि हम तो एक को ही पकड़कर जिएंगे, तो आपको यह भी मानना होगा कि आप एक ही पैर से चलेंगे, एक ही पतवार से अपनी नाव खे लेंगे। कभी एक ही पतवार से नाव खेकर देखी? न देखी हो, तो जरूर नदी पर जाकर देखना; उससे बड़ा अनुभव होगा। जब आप एक ही पतवार से नाव को खेओगे, तो वह गोल-गोल चक्कर लगाने लगेगी। जाएगी कहीं नहीं। ऐसी ही जिंदगी है। जाती कहीं नहीं, होता कुछ भी नहीं, चक्कर ही चक्कर! इसीलिए हमें दोनों पतवारें चाहिए। दोनों पतवारों के बीच नाव तीर की तरह चलने लगती है।

अगर आप चाहते हैं कि सच में आपके जीवन का फूल खिले, तो कांटों से दूर रहने की आदत छोड़ दें। ज्योति अंधेरे में ही जगमगाती है। पत्थर पर जब छेनी चलती है, तभी तो मूर्तियां निर्मित होती हैं।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

साल 2024 में 14 संघर्षों में 36 हजार से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। युद्धों के भी नियम होते हैं, जिनका सभी को सम्मान करना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अनुलोम-विलोम

न्यूनतम समर्थन मूल्य

किसानों के लिए हितकारी यह बढ़ोतरी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन (मार्केटिंग) सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह कृषि और किसान-कल्याण की दृष्टि से एक स्वागतयोग्य कदम है। सुखद यह है कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ उत्पादन-लागत घटाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत ब्याज छूट को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी है।

पिछले वर्ष से तुलना करें, तो इस बार एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, जिसके बाद रागी में 596 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 589 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के दाम में 579 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी में वृद्धि से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। कहना गलत नहीं होगा कि खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। एमएसपी में यह वृद्धि देश भर की औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना सुनिश्चित करते हुए की गई है। वास्तव में, सरकार का यह निर्णय हमारे देश के किसानों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम कहा जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, जिसके बाद मक्का (59 प्रतिशत), तुअर (59 प्रतिशत) और उड़द (53 प्रतिशत) का स्थान है। शेष फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50 प्रतिशत होने का अनुमान है।

साफ है, आज कृषि और किसान-कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। किसानों को आज क्रेडिट कार्ड के तहत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनको सस्ते खाद, बीज दिए जा रहे हैं। उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। इस पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। अब जरूरत यह है कि इस पर प्रभावी निगरानी रखी जाए और इसे सही तरीके से लागू किया जाए।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

सरकारी दामों पर नहीं बिकती फसलें

सरकार ने सोयाबीन के लिए एमएसपी बढ़ाकर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि मंडी में यह किस भाव में बिकता है, यह सभी को पता है। जब फसलें समर्थन मूल्य से 1,000-1,500 रुपये कम कीमत पर बिक रही हैं, तब समर्थन मूल्य बढ़ाने से क्या फायदा? पूरे देश में किसान इसीलिए आंदोलन करते रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। मंडी में बोली इसी मूल्य से शुरू हो और इससे कम में खरीदी करने वाले व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मगर कुछ लोग किसानों को खालिस्तानी और गद्दार कहने लगते हैं। ऐसे में, यही पंक्ति गुनगुनाने का मन करता है- किसान तू रहेगा मौन, तो तेरी सुनेगा कौन?

सचिन पटेल, टिप्पणीकार

जब देश में खाद्यान्न का अभाव था और सरकार को विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था, जो आमतौर पर कम गुणवत्ता का होता था, तब तत्कालीन सरकार ने एमएसपी व्यवस्था लागू कर फसलों को संरक्षण देकर किसानों से देश का भंडार भरने का आग्रह किया। इस प्रकार हरित क्रांति के दौर में किसानों ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। सीएसीपी की रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार चंद फसलों का मूल्य तय करती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इससे कम कीमत पर फसल के बिकने पर किसानों को खासा नुकसान होता है। यह समर्थन मूल्य हमारे देश में केवल 22 अनिवार्य फसलों के लिए तय किया जाता है, जिनमें फल या साग-सब्जी शामिल नहीं हैं। 2015 में गठित शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट की मानें, तो केवल छह फीसदी किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी शेष बचे 94 प्रतिशत किसान इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसे आसान भाषा में कहें, तो सरकारी खरीद के अतिरिक्त किसानों को मंडी या खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत यह प्रावधान भी है कि मंडी में पहली बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होनी चाहिए, परंतु वास्तव में इसका पालन नहीं होता। बोली समर्थन मूल्य के नीचे से शुरू होती है और किसान जरूरी लाभ से वंचित रह जाता है। ऐसे में, यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बने, तो किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा, जिससे उनकी आय सुनिश्चित हो सकेगी। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि देश की आधी से अधिक आबादी खेती से अपना गुजारा कर रही है। अगर उनके हाथ खाली रहे, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा।

राहुल राज, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 2 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन
मनुष्य का पतन कार्य की अधिकता से नहीं वरन कार्य की अनियमितता से होता है।
-अज्ञात

सच का सामना

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सिंगापुर में जो कहा है वह सबकी आंखें खोल देने वाला है। इससे साबित होता है कि जब दो देशों के बीच छिटपुट सैन्य संघर्ष की स्थिति हो तो ऐसे में असत्य अवधारणाओं और समर्थक मीडिया के सहारे ही बढ़त नहीं ली जा सकती। तथ्यों को दबाना संभव नहीं होता और वे किसी न किसी रास्ते बाहर आ ही जाते हैं। 'ब्लूमबर्ग टीवी' को दिये एक साक्षात्कार में जनरल चौहान ने पड़ोसी देश के साथ चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष में साफ ब्योरा न देते हुए भारतीय पक्ष को हुए नुकसान की एक तरह से स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है। उनका कहना था विमान गिरे यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे यह जानना जरूरी है। प्रारंभिक नुकसान के कारणों का पता लगाने के बाद भारत ने अपनी रणनीति में सुधार किया, लंबी दूरी का लक्ष्य कर अपने सभी लड़ाकू विमान उड़ाए और पाकिस्तान में काफी अंदर तक सटीक हमले किए जिससे पाक संघर्ष विराम की गुहार लगाने पर मजबूर हुआ। हालांकि उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को 'सरासर गलत' बताया। जनरल चौहान की टिप्पणी से वायुसेना के वायु संचालन महानिदेशक, एयर मार्शल ए के भारती की उस बात को भी बल मिला कि 'नुकसान लड़ाई का एक हिस्सा है।' भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में छह मई की देर रात 'ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसी लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हमले के बाद चार दिन तक सैन्य टकराव हुआ। दोनों देशों के बीच दस मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। इस सारे मामले में विपक्ष और देशवासियों को सही तथ्यों से अनभिज्ञ रखने की केंद्र सरकार की नीति सवालों के घेरे में है। अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति के भारत-पाक में सीजफायर कराने के दावों ने पहले हास्यास्पद स्थिति पैदा की हुई है। वायु सेना प्रमुख की हाल में रक्षा उपकरणों को लेकर किए गए वादों को समय से पूरा न करने संबंधी टिप्पणी भी चिंताजनक है। सीडीएस की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा है कि वह देश को सच-सच बताए कि पाकिस्तान के साथ चार दिन तक सैन्य टकराव में कितना नुकसान हुआ। पार्टी ने 1999 में करगिल समीक्षा समिति के गठन की तर्ज पर समीक्षा समिति का सवाल उठाया है। रक्षा विशेषज्ञ 'उपयुक्त युद्ध सामग्री नहीं होने के कारण' सैन्य संघर्ष की पहली रात नुकसान होने की बात कह रहे हैं। सब कुछ बहुत उलझा हुआ और चिंताजनक है।

बराबरी के छलावे

प्रधान न्यायाधीश बीआर गंवई ने कहा है कि न्यायपालिका व विधायिका का मौलिक कर्त्तव्य है, देश के उस आखिरी नागरिक तक पहुंचना जिसे न्याय की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब भी संकट आया, भारत एकजुट रहा। इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता चैंबर भवन व मल्टीलेवल पार्किंग के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, संविधान लागू होने पिछत्तर वर्ष की यात्रा में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका ने सामाजिक-आर्थिक समानता लाने में बड़ा योगदान दिया है। बार व बेंच को सिक्के के दो पहलू बताते हुए मिल कर काम न करने पर रथ के आगे न बढ़ने की चर्चा भी की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं की समस्याएं दर करने के लिए केंद्र के सतत प्रयासरत रहने और अधिवक्ता निधि की राशि बढ़ा कर पांच लाख करने की बात की। पेड़ों के नीचे बैठ कर काम करने वाले वकीलों की चर्चा करते हुए उन्होंने एयरकंडीशनर उनके गुस्से को ठंडा करने जैसी बात की। बेशक, यह केवल उच्च न्यायालय परिसर की बात थी। देश के किसी भी मुख्यमंत्री को विचारना चाहिए कि अमूमन वकीलों तो क्या जिला जजों के लिए न तो ढंग की बैठने की जगह है, न स्वच्छ/शीतल जल है। एसी तो बहुत दूर की बात है। प्रधान न्यायाधीश द्वारा की गई मुख्यमंत्री की तारीफ में इसका ख्याल किया जाना लाजिमी था क्योंकि जिलों में कार्यरत वकीलों व न्यायाधिकारियो को भी शीर्षाधिकारियों से उम्मीद होती है कि वे उनकी दशा पर भी दो बाले बोलें। यह पहला मौका था जब प्रधान न्यायाधीश के तौर पर वे इलाहाबाद गए थे। हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद आगे की बात कहने पर भी जोर दिया। जैसा कि वे इसी वर्ष नवम्बर में रिटायर हो रहे हैं। देश की मौजूदा राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। संविधान समानता की दिशा तो दे रहा है मगर व्यावहारिक तथ्य यह भी है कि अभी भी बड़ा वर्ग आर्थिक-सामाजिक तौर पर वंचित है जिन्हें राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के नजरिए से आंकते हैं। देश का वह आखरी नागरिक आज भी कातर भाव से शीर्ष पर बैठे लोगों को ताक रहा है जिसे न तो अपने अधिकारों का ज्ञान है, न ही उसकी तूती की आवाज में दम है।

परिधि/राजीव मंडल

फर्जी खबरों की 'बमबारी'

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान के बयान की देश और दुनिया के बाकी देशों में काफी चर्चा हो रही है। हमारे यहां की मीडिया ने चौहान के इस बयान को प्रमुखता से छापा कि, 'विमान गिरे, ये महत्त्वपूर्ण नहीं। क्यों गिरे, यह जानना जरूरी है।' स्वाभाविक रूप से उनका यह बयान काफी अहम है। क्योंकि अब इस बात पर बहस की कोई वजह नहीं दिखती कि। मगर उनकी कही दूसरी बातों का अर्थ ज्यादा संजीदा है।

चौहान ने कहा कि 'जंग में गलत जानकारी और अफवाहें एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारे जवानों का 15 फीसद वक्त फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हो गया।' साफ है कि हमें इस मामले में और ज्यादा परिपक्व, सतर्क, समझदार और समृद्ध होना होगा। क्या हम इस बार पाकिस्तान के फैलाए गए झूठे 'चक्रव्यूह' में फंस गए थे। सीडीएस के बयान से तो ऐसा ही लगता है। शायद इसी कारण से उन्होंने इस बात को दोहराया कि हमारी रणनीति यह रही कि बिना जल्दबाजी किए पुख्ता तथ्यों व सबूतों के साथ अपनी बात रखी जाए। शांगरी-ला संवाद में 'भविष्य की चुनौतियों के लिए रक्षा नवाचार समाधान' पर चौहान ने कई सारे सवालों पर दिलदारी से अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विकसित भू-राजनीतिक गतिशीलता और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों पर प्रकाश डाला, जिससे युद्ध की प्रकृति को फिर से परिभाषित हो रही है।

क्या फर्जी खबरें पोस्ट करना वाकई 'सूचना युद्ध' (इनफार्मेशन वारफेयर) का हिस्सा है? इसका जवाब हां होगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मिसाइल हमल शुरू हुआ, उसी समय से गलत जानकारियों की 'बमबारी' भी शुरू हो गई। लाजिमी है इससे तुरत-फुरत पार पाना भारतीय सेना के लिए आसान न था। और इस बात की तस्दीक खुद सीडीएस ने कर भी दी। दरअसल, 'सूचना युद्ध' महत्त्वपूर्ण है, यह आधुनिक युद्ध तकनीक का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए समन्वित प्रयास होने चाहिए। सोशल मीडिया आज के वक्त में कितना आवारा और गैर जवाबदेह हो चला है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और जब बात दो देशों के बीच संघर्ष की हो तो इसके कसैलेपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल, देखना होगा, चौहान की कीमती सलाह को लेकर सरकार कितनी जल्दी एक्शन मोड में आती है।

रक्षा परियोजनाओं में देरी क्यों

सामयिक

विनीत नारायण

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 29 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक सभा में रक्षा परियोजनाओं में देरी को लेकर महत्त्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, 'टाइमलाइन बड़ा मुद्दा है। मेरे विचार में एक भी परियोजना ऐसी नहीं है, जो समय पर पूरी हुई हो। कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय जानते हैं कि यह सिस्टम समय पर नहीं आएगा। फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।' यह बयान भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रही प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।

एयर चीफ मार्शल सिंह ने अपने बयान में विशेष रूप से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. द्वारा तेजस Mk1A फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी का उल्लेख किया। यह देरी 2021 में हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें 83 तेजस Mk1A जेट्स की डिलीवरी मार्च, 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक एक भी विमान डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने तेजस Mk2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में प्रोटोटाइप की कमी और देरी का भी जिक्र किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद, जिसे उन्होंने 'राष्ट्रीय जीत' करार दिया गया है, उनके बयान का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पहली बार नहीं है जब HAL की आलोचना हुई है। फरवरी, 2025 में एयरो इंडिया 2025 के दौरान एयर चीफ मार्शल सिंह ने HAL के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, 'मुझे HAL पर भरोसा नहीं है, जो बहुत गलत बात है।' यह बयान एक अनौपचारिक बातचीत में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इसने रक्षा उद्योग में गहरे मुद्दों को उजागर किया। रक्षा परियोजनाओं में देरी के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ संरचनात्मक और कुछ प्रबंधन से संबंधित हैं। तेजस Mk1 की डिलीवरी में देरी का एक प्रमुख कारण जनरल इलेक्ट्रिक से इंजनों की धीमी आपूर्ति है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में समस्याएं विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगे प्रतिबंधों ने HAL की उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। सिंह ने HAL को 'मिशन मोड' में न होने के लिए आलोचना की।

उन्होंने कहा कि HAL के भीतर लोग अपने-अपने साइलो में काम करते हैं, जिससे समग्र तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह संगठनात्मक अक्षमता और समन्वय की कमी का संकेत है। सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही यह

स्पष्ट होता है कि समय सीमा अवास्तविक है। फिर भी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू से ही खराब हो जाती है। यह एक गहरी सांस्कृतिक समस्या को दर्शाता है, जहां जवाबदेही की कमी है। हालांकि सरकार ने AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित रही है। इससे HAL और DRDO जैसे सार्वजनिक उपक्रमों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है, जो अक्सर समय सीमा पूरी करने में विफल रहते हैं।

भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। डिजाइन और विकास में देरी, जैसे कि तेजस Mk2 और AMCA के प्रोटोटाइप की कमी, भी परियोजनाओं को और पीछे धकेलती है। रक्षा परियोजनाओं में देरी का भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में भारतीय वायु सेना के पास 42.5 स्क्वाड्रनों की स्वीकृत ताकत के मुकाबले केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। तेजस Mk1A जैसे स्वदेशी विमानों की देरी और पुराने मिग-21 स्क्वाड्रनों का डीकमीशनिंग इस कमी को और गंभीर बनाता है। देरी से रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति भी प्रभावित होती है।

सिंह ने कहा, 'हमें केवल भारत में उत्पादन की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि डिजाइन और विकास भी भारत में करना चाहिए।' देरी न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को कमजोर करती है, बल्कि रक्षा उद्योग में विश्वास को भी प्रभावित करती है। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे हालिया सैन्य अभियानों ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक युद्ध में हवाई शक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, और इसके लिए समय पर डिलीवरी और तकनीकी उन्नति अनिवार्य है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान ने रक्षा क्षेत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। रक्षा कॉन्ट्रैक्ट्स में यथार्थवादी समय सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। सिंह ने सुझाव दिया, 'हमें वही वादा करना चाहिए जो हम हासिल कर सकते हैं।' इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले गहन तकनीकी और लॉजिस्टिकल मूल्यांकन की आवश्यकता है। AMCA प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी सकारात्मक कदम है। निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में और अधिक शामिल करने से HAL पर निर्भरता कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। HAL और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को 'मिशन मोड' में काम करने के लिए संगठनात्मक सुधार करने चाहिए। इसके लिए समन्वय, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कर्मचारी प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। इंजन और अन्य महत्त्वपूर्ण घटकों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी विकास पर ध्यान देना होगा। रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज करने की आवश्यकता है ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

एयर चीफ मार्शल सिंह का बयान रक्षा क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाए बैठी समस्याओं को उजागर करता है। उनकी स्पष्टवादिता न केवल जवाबदेही की मांग करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत को आत्मनिर्भर और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। तेजस Mk1A, Mk2 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की रक्षा क्षमता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें देरी न केवल हमारी फौज की तत्परता को प्रभावित करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। सरकार, रक्षा उद्योग और निजी क्षेत्र को मिल कर इन चुनौतियों का समाधान करना होगा ताकि भारत न केवल उत्पादन, बल्कि डिजाइन और विकास में भी आत्मनिर्भर बन सके। सिंह का यह बयान चेतावनी तो है ही, लेकिन साथ ही रक्षा क्षेत्र को 'सर्वश्रेष्ठ' करने की दिशा में एक अवसर भी है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> एयर चीफ मार्शल सिंह का बयान रक्षा क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाए बैठी समस्याओं को उजागर करता है। उनकी स्पष्टवादिता न केवल जवाबदेही की मांग करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत को आत्मनिर्भर और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। जो प्रोजेक्ट्स भारत की रक्षा क्षमता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, उनमें देरी न केवल हमारी फौज की तत्परता को प्रभावित करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है

भारत में लुप्तप्राय: प्रजातियां

- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने साल 2020 में रेड लिस्ट जारी कर बताया था कि जानवरों की 500 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त यानी लुप्तप्राय: हैं
- लुप्तप्राय का अर्थ क्या है? यह वह प्रजाति है, जो किसी समय किसी क्षेत्र में पाई जाती थी लेकिन अब इसकी संख्या 50 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है
- विलुप्तप्राय लिस्ट में एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन, एक सींग वाला गैंडा, हिम तेंदुआ और बंगाल टाइगर के साथ अन्य प्रजातियों के नाम शामिल हैं

(मीडिया इनपुट्स)

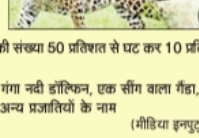

वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने सार्वजनिक तौर पर सच बोलने का साहस दिखाया है। आत्मालोचना को सुधार की पहला कदम माना जाता है। क्या हमारा सिस्टम और उसके संचालक सुधरेंगे या सिर्फ अग्निवर्षी बयानबाजी करते रहेंगे?

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

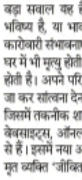

उगता भविष्य या भावनात्मक व्यापार

डेथ टेक्नोलॉजी उद्योग | अमरपाल सिंह वर्मा

इन दिनों दक्षिण भारत का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो एक विवाह समारोह का है, जिसमें दूल्हे के दिवंगत पिता को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है। वह अपनी पत्नी और बेटों से मिलते और समारोह में शामिल होकर भोजन करते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद उन्हें फिर 'स्वर्ग' प्रस्थान करते दिखाया गया है। वीडियो को देख अनेक लोग हैरान हैं। कई लोग इसे देख भावुक भी हो उठते हैं पर इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल, यह वीडियो एआई तकनीक से बनाया गया है जिसने डिजिटल क्रांति की तेज लहरों में बहते हुए अब जीवन की अंतिम सीमा यानी मृत्यु को भी तकनीकी प्रयोगों का हिस्सा बना दिया है। ये प्रयोग पश्चिमी देशों में खूब फल-फूल रहे हैं, और इसकी बदौलत वहां बाकायदा एक बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है, जिसे 'डेथ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज' नाम दिया गया है। दक्षिण भारत के वीडियो से पता चलता है कि अब भारत में भी इसके अंकुर फूटने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यह हमारे समाज में उगता हुआ भविष्य है, या भावनात्मक व्यापार? भारत में इसके लिए कारोबारी संभावनाएं तलाशने के लिए काम हो रहा है। जिस घर में भी मृत्यु होती है, वहां के लोगों को सांत्वना की जरूरत होती है। अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों के घर तक जा कर सांत्वना देना हमारे समाज का स्थापित लोकाचार है, जिसमें तकनीक शामिल हो गई है। कई डिजिटल श्रद्धांजलि वेबसाइट्स, ऑनलाइन श्राद्ध और पूजा सेवाएं वगैरह पहले से हैं। इसमें नया अवतार है होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें मृत व्यक्ति 'जीवित' दिखाई देता है।

बड़ा सवाल यह है कि इस उद्योग के फैलने का समाज पर असर क्या होगा? क्या यह वास्तव में भावनात्मक सुकून का जरिया है, या माननीय संवेदनाओं से खेल कर पैसा बनाने का धंधा? बहरहाल, भले ही इस तकनीक का उद्देश्य श्रद्धा और स्मृति को बनाए रखना है, परंतु इसके दुष्परिणामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन दर्शन में मृत्यु स्वाभाविक चरण और शाश्वत सत्य है, जिसका घटना लाजिमी है। हमें मृत्यु को स्वीकार कर आगे बढ़ना सिखाया जाता है, फिर भी यदि हम अपने परिजनों को पुनर्जीवित होते देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हम मृत्यु को स्वीकार कर पा रहे हैं?

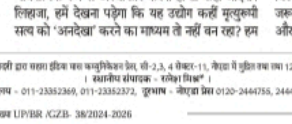

श्रद्धांजलि अर्पित करना अलग बात है पर जब हम तकनीक से मृतकों को 'पुनर्जीवित' करते हैं, तो क्या हम सच में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या अपने मोह और मृत्यु को अस्वीकार करने को तकनीकी जामा पहना रहे हैं? परिजन की मृत्यु को स्मृतियों में सहेजना और उससे प्रेरणा लेना तो समझ में आता है पर उस मृत्यु को 'न होने' जैसा दिखाना घट चुके सच को भावनात्मक रूप से अस्वीकार करना ही तो कहा जाएगा। लिहाजा, हमें देखना पड़ेगा कि यह उद्योग कहीं मृत्युरूपी सत्य को 'अनदेखा' करने का माध्यम तो नहीं बन रहा? हम दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए पारंपरिक धार्मिक विश्वासों के आधार पर क्रिया-कलाप भी करते हैं। आत्मा को मोक्ष मिले, इसके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। किसी की मृत्यु के उपरांत हम उसकी आत्मिक शांति के पक्ष में हैं, तो उसे बार-बार वर्चुअली बुलाना, एआई के जरिए उससे 'संवाद' करना, क्या आत्मा को बांधने के क्रियाकलाप में नहीं गिना जाएगा? क्या यह सब उस आत्मा की शांति में हस्तक्षेप नहीं होगा? जिस व्यक्ति के मोक्ष की हम कामना कर चुके, उसे इस प्रकार रूबरू कर लेना क्या पुनः आह्वान नहीं कहलाएगा?

दिवंगतों के होलोग्राम को बार-बार देखना क्या वियोग के दुःख को बढ़ाएगा नहीं? हमारे देश, जहां मानसिक बीमारियों को बीमारी ही नहीं माना जाता है, में यह तकनीक परेशानी को बढ़ाने का सबब बन सकती है। इससे अनेक वृद्धों, भावुक व्यक्तियों, मानसिक रूप से संवेदनशील और दिमागी तौर पर अस्वस्थ लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। होलोग्राम पर मृतकों को बार-बार देखना और चैटबॉट्स के जरिए उनसे 'बातें करना' ऐसे लोगों को भ्रमित कर सकता है। डेथ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भारत में अपने आरंभिक चरण में है लेकिन इसके बीज बोए जा चुके हैं।

मृत्यु शाश्वत सत्य है और हमारे यहां इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने पर जोर दिया जाता है पर बड़ा सवाल है कि क्या यह उद्योग इस विचार के विरुद्ध नहीं है? निश्चित रूप से यह उद्योग मृत्यु का बाजारीकरण है। बाजारवाद के कंधों पर सवार तकनीक के जरिए श्रद्धा का अर्थ ही बदल जाएगा। जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा एवं एआई के जरिए उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उसके लिए पैसा लिया जाए तो यह श्रद्धा नहीं, एक उत्पाद ही तो कहलाएगा। यह उद्योग उस विचार के विपरीत है जो कहता है कि मिट्टी में मिल जाना ही जीवन की पूर्णता है। क्या यह आत्मा की मुक्ति के विरुद्ध नहीं है? तो क्या इस उद्योग को नकार देना चाहिए? जरूरी नहीं कि हम इसे नकारें। नकारने की बजाय हमें श्रद्धा और तकनीक के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

समाज | श्रीराम शर्मा आचार्य

हम में से हर व्यक्ति अपने को समाज का अविच्छिन्न अंग माने। एक नाव में बैठे लोग जिस तरह एक साथ डूबते या पार होते हैं, वैसी ही मान्यता अपनी रहे। स्वार्थ और परमार्थ को परस्पर गूंथ दें। मिल जुल कर काम करने और मिल बांट कर खाने की आदत डाली जाए। मनुष्यों के बीच सज्जनता, सद्भावना एवं उदार सहयोग की परंपरा चले। दान, विपत्ति एवं पिछड़ेपन से ग्रस्त लोगों को पैरों पर खड़े होने तक के लिए दिया जाए। उसका सतत प्रवाह सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए ही नियोजित हो। साधारणतया मुफ्त में खाना-खिलाना अनैतिक समझा जाए। इसमें पारिवारिक-सामाजिक प्रीति भोजों का जहां औचित्य हो, वहां अपवाद रूप से छूट रहे। भिक्षा व्यवसाय पनपने न दिया जाए। दहेज, मृतक भोज, सदावर्त धर्मशाला आदि ऐसे दान जो मात्र प्रसन्न करने भर के लिए दिए जाते हैं, और उस उदारता के लाभ समर्थ लोग उठाते हैं, अनुपयुक्त माने और रोके जाएं। साथ ही, हर क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए उदार श्रमदान और धनदान को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए। किसी मान्यता या प्रचलन को शाश्वत या सत्य न माना जाए, उन्हें परिस्थितियों के कारण बना समझा जाए। उनमें जितना औचित्य, न्याय और विवेक जुड़ा हो उतना ग्राह्य और जो अनुपयुक्त होते हुए भी परंपरा के नाम पर गले बंधा हो, उसे उतार फेंका जाए। समय-समय पर इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण होते रहना चाहिए और जो असामयिक, अनुपयोगी हो उसे बदल देना चाहिए। इस दृष्टि से लिंग भेद, जाति भेद के नाम पर चलने वाली विषमता सर्वथा अग्राह्य समझी जाए। सहकारिता का प्रचलन हर क्षेत्र में किया जाए। अलग-अलग पड़ने की अपेक्षा सम्मिलित प्रयत्नों और संस्थानों को महत्त्व दिया जाए। संयुक्त परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त विश्व को लक्ष्य बना कर चला जाए। विश्व परिवार का आदर्श कार्यान्वित करने का ठीक समय यही है। सभी प्रकार के बिलगावों को निरस्त किया जाए। व्यक्ति की सुविधा की तुलना में समाज व्यवस्था को वरिष्ठता मिले। प्रशंसा ऐसे ही प्रयत्नों की हो जिन्हें सर्वोपयोगी कहा जाए। व्यक्तिगत समृद्धि, प्रगति एवं विशिष्टता को श्रेय न मिले। उसे कौतूहल मात्र समझा जाए।

रीडर्स मेल

लालच बुरी बला

बहुत से लोग रोज खाने-कमाने वाले होते हैं। वे अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए रखते हैं। ऐसे में उन्हीं के कुछ परिचित उकसाने वाले होते हैं। वे अपनी स्कीमों के बारे में बताते हैं। आपका पैसा कुछ समय में दुगना हो जाएगा। आपको सस्ते में प्लॉट भी मिलेगा। ऐसी स्कीमों में लोग फंस जाते हैं। इसके दुष्परिणाम जल्द ही सामने आने लगते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वे दिनदहाड़े ठगी का शिकार हो गए हैं। फिर मारते रहो अंधेरे में तीर। गया पैसा वापस मिल जाए तो बड़ी बात समझो। जिन्हें ये पैसा सम्मान से देते थे वापसी में वही अपमान के पात्र हो गए। सही तो यह है कि पैसा धीरे-धीरे बढ़ता है। इसे बैंक में जमा रकम से आसानी से जाना जा सकता है। फिर भी आप अपना पैसा किसी की बातों में आकर लगाते हैं, तो दोषी आप हैं। ऐसे लोगों पर सूक्ति फिट है लालच बुरी बला। तो गांठ बांध लें कि अपना पैसा पूरी तरह जानकार होकर निवेश करेंगे।

सीमा गुप्ता, बरेली

चीतों की सुरक्षा के लिए पहल

कुनो के नेशनल पार्क में विगत वर्ष चीतों की मौत से सबक लेकर इस बार चीतों को बचाने की सराहनीय पहल कुनो के चीतों को बचाने में अग्रसर रहेगी। कुनो के नेशनल पार्क में खुले जंगलों में विचरण कर रहे 16 चीतों को मानसून से पहले ही जून के पहले सप्ताह में वेक्सीनेट किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए मानसून से पहले वेक्सीनेट करने का निर्णय हमारे चीतों को बचाने में यकीनन मददगार साबित होगा। उल्लेखनीय है कि सत्र 2023 में बारिश के दौरान इन्फेक्शन से तीन चीतों की मौत हो गई थी। इस चूक को दोहराने से बचने के लिए सभी चीतों को मानसून से पहले ही वेक्सीनेट करने का निर्णय निश्चित ही कारगर और फायदेमंद होगा। कुछ चीतों को बाड़े में बंद भी किया जा सकता है, और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। कुछ भी हो कुनो के चीतों के जीवन के संरक्षण और स्वास्थ्य की सक्रियता प्रजाति को जीवंत रखेगी। चीतों की तरह पालतू जानवरों और अन्य जानवरों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी कारगर नीति-रीति जरूरी हो जाती है। कुछ भी हो यह सराहनीय पहल है। निश्चित ही चीतों का परिवार स्वास्थ्य परीक्षण एक सार्थक पहल मानी जाएगी।

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

आवारा पशुओं को भी हटाया जाए

देश की सड़कों से अतिक्रमण के साथ ही आवारा पशुओं को भी हटाया जाए। देश भर से आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों एवं बुजुर्गों को काटने की घटना रोज सुनने एवं देखने को मिलती हैं, जिन पर शहर के लोगों में बड़ी नाराजगी भी देखी जा सकती है। दिल्ली में तो बाकायदा एक पूर्व सांसद द्वारा आंदोलन चलाया गया है, और यह मुद्दा कोर्ट में भी जा पहुंचा है लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। राजधानी से लेकर अन्य शहरों में भी बंदरों का आतंक भी कम नहीं है। देश की राजधानी में अनेक जगह पर बंदरों का झुंड दिखाई दे जाता है, और आने-जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इसको आस्था के साथ भी जोड़ देते हैं। हापुड़ में एक दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया। इन बंदरों ने छात्रा को इतना आतंकित कर दिया था कि उसको छत से नीचे कूदना पड़ा था जिस कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सरकार को जरूर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि लोगों की मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 286
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नरूंस हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 90

वृद्धि को सहारा

गत सप्ताह जारी राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों ने अधिकांश अर्थशास्त्रियों को सकारात्मक रूप से चौंकाया। वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वास्तविक अर्थों में 6.5 फीसदी बढ़ी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी अपने दूसरे अग्रिम अनुमानों में इसके इसी स्तर पर रहने की बात कही थी। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर के 6 फीसदी से नीचे रहने के कारण चिंता की स्थिति बनी। बहरहाल, अर्थव्यवस्था वर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर स्थिति में आ गई। खासतौर पर अंतिम तिमाही में। चौथी तिमाही के दौरान सकल मूल्यवर्धन 6.8 फीसदी रहा और इसमें कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों का योगदान रहा। विनिर्माण क्षेत्र इस तिमाही में भी केवल 4.5 फीसदी की दर से बढ़ा। मांग की बात करें तो पूरे साल के दौरान निजी अंतिम खपत व्यय 7.2 फीसदी बढ़ा जबकि इससे पिछले साल यह 5.6 फीसदी बढ़ी थी। निवेश में केवल 7.1 फीसदी का इजाफा हुआ जबकि इससे पिछली तिमाही में यह 8.8 फीसदी बढ़ा था। वर्ष की शुरुआत धीमी निवेश गतिविधि से हुई लेकिन दूसरी छमाही में इसने गति पकड़ ली।

यह सही है कि वृद्धि 6.5 फीसदी रही लेकिन यह भी ध्यान देने लायक है कि यह 2023-24 के 9.2 फीसदी के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा 2021-22 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से इस वर्ष विस्तार की गति सबसे धीमी रही। वर्ष के दौरान कई अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि महामारी के झटके से उबरने के बाद वृद्धि सामान्य स्तर पर लौट आई है। चालू वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मॉनसून जल्दी आ गया है और बारिश के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। उच्च कृषि उत्पादन न केवल वृद्धि में सीधा योगदान करेगा बल्कि ग्रामीण आय में भी इजाफा करेगा। इससे मांग को समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर निजी खपत में सुधार के संकेत हैं लेकिन यह देखने की बात होगी कि यह टिकाऊ है या नहीं। चाहे जो भी हो, उच्च कृषि उत्पादन और कम खाद्य मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी को नीतिगत राहत का अवसर देंगे।

विश्लेषकों का अनुमान है कि एमपीसी मौजूदा चक्र में नीतिगत ब्याज दरों में 50 से 100 आधार अंकों की और कटौती करेगी। वास्तविक कमी इस बात पर निर्भर करेगी कि एमपीसी आने वाली तिमाहियों में मुद्रास्फीति के किस प्रकार के उभार की उम्मीद करती है और संभावित वृद्धि को लेकर क्या अनुमान लगाती है। अगर मुद्रास्फीति के परिणाम लक्ष्य के करीब रहते हैं तो एमपीसी शायद नीतिगत समायोजन के साथ वृद्धि को गति दे। बहरहाल, काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बाहरी माहौल क्या करवट लेता है? अमेरिका और अन्य जगहों पर उच्च बॉन्ड प्रतिफल भी एमपीसी के विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में बाहरी वित्तीय और आर्थिक अनिश्चितताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित करेंगी। अमेरिका की एक अदालत ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा आपात उपायों का इस्तेमाल करके लगाए गए उच्च शुल्कों पर रोक लगाने का निर्णय दिया है। बहरहाल, एक अन्य अदालत ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है। इस बीच ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है।

ट्रंप प्रशासन के कदमों से उत्पन्न वैश्विक व्यापार और आर्थिक अनिश्चितता जारी रह सकती है। इस बीच विभिन्न देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। इस बात की संभावना नहीं है कि ट्रंप अपनी टैरिफ योजना को त्यागेंगे। ऐसे में कानूनी जटिलताएं अनिश्चितता में और इजाफा करेंगी। ऐसी हालत में निर्यात और निवेश पर असर हो सकता है। इसका असर वृद्धि पर भी पड़ेगा। गत सप्ताह के आंकड़े यह भी बताते हैं कि सरकार गत वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रही। इस वर्ष भी उससे यही उम्मीद है। उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन से वृद्धि को इस वर्ष भी मदद मिलती रहेगी। ऐसे में वृद्धि को सबसे बड़ा जोखिम बाहरी होगा। भारत इस माहौल से कैसे निपटता है और सुधारों का क्रियान्वयन करके कारोबारी चक्र में कैसे सुधार करता है, इससे ही मध्यम अवधि में हमारी वृद्धि का दायरा क्या होगा।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पांचवें सितारे का बोझ

मुनीर ने इमरान खान को कैद किया, कठपुतली संसद के जरिये संविधान को तोड़ मरोड़कर अपना सेवा विस्तार हासिल किया। अब उनके पांचवें सितारे की चमक से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

अपने सीने पर सजे पांच सितारों के साथ पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो वह चार सितारों के साथ नहीं कर सके? एक पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल बनकर आखिर ऐसा क्या कर सकता है जो वह केवल जनरल के रूप में नहीं कर सका? यह कहना लुभावना हो सकता है कि यह उनकी कॉलर, टोपी, कार आदि को और सुसज्जित करेगा लेकिन यह सवाल तो रहा उनके भी दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा होगा? उन्हें पता है कि इस पांचवें सितारे के हासिल होने के बाद कुछ करना होगा। क्या भारत को चिंतित होना चाहिए?

इसका संक्षिप्त जवाब है कि भारत को पाकिस्तान की सेना से हमेशा चिंतित होना चाहिए और वह होता भी है। यह एक अलग चिंता का विषय है कि व्यवस्था के भीतर या उसके बाहर इस अजीबोगरीब पदोन्नति के बाद शहबाज शरीफ की इस व्यवस्था में क्या जगह बनती है?

वह अपने पांचवें सितारे के साथ क्या करेंगे जो पाकिस्तान और इस उपमहाद्वीप के इतिहास में केवल दूसरी बार हासिल हुआ है (हमारे तीन पांच सितारा जनरलों करियप्पा, मानेकशॉ और अर्जन सिंह को रस्मी बेटन सौंपा गया था) और आधुनिक सेनाओं में यह अत्यंत दुर्लभ है। किसी और देश से ऐसा उदाहरण चुनना हो तो मिस्र के अब्देल फतह अल-सीसी का नाम लिया जा सकता है।

यहां तक कि शक्तिशाली देश अमेरिका ने भी आइजनहॉवर, पैटर्न, ब्रैडले और शर्मन जैसे नामों के बाद इस उपाधि का इस्तेमाल बंद कर दिया। यकीनन आसिम मुनीर इस उपाधि के बाद कुछ करना चाहेंगे। मैं यहां ईदी अमीन का उदाहरण देना चाहूंगा और 'ब्रिटिश साम्राज्य को फतह करने वाला' जैसी कोई उपाधि हो सकता है, लेकिन यह मजाक का वक्त नहीं है।

असैन्य सरकार को हटाकर सत्ता संभालना पाकिस्तान में इतना साधारण काम है कि शायद उनको ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े। पाकिस्तान को लेकर हमारा तमाम राजनीतिक और सामरिक विश्लेषण इस बात पर केंद्रित रहना चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर से किस तरह अलग होंगे? जनरल क्या कर सकते हैं यह हमने 16 अप्रैल को प्रवासी पाकिस्तानियों को दिए उनके संदेश और पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई घटना में देख सकते हैं। अपने भाषण का एक वादा जो उन्हें अभी पूरा करना है वह है पाकिस्तान को एक 'हार्ड स्टेट' बनाने का। प्रचार तंत्र के सहारे जीत के जश्न से इतर उनको पता है कि उनकी सेना को गहरा नुकसान हुआ है। भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के तथ्यरहित दावे कुछ समय के लिए पाकिस्तान की जनता को खुश कर सकते हैं। इसके बावजूद सिंधु नदी के पूरब में ध्वस्त हवाई ठिकानों और जैश-लश्कर के ठिकाने के मलबे में बदले होने की तस्वीरें ही छाई रहेंगी। वह पांचवे सितारे के साथ चाहे जितना सीना ठोक लें, जमीनी तथ्य नहीं बदलने वाले। वह यकीनन 'कुछ और' करना चाहेंगे। वास्तव में उन्हें इसकी जरूरत भी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह हमारी उम्मीद से जल्दी कुछ कर गुजरेंगे। अतीत में हम इसे पाकिस्तानी सेना की 'सात साल वाली खुजली' कहते रहे हैं जहां हर बड़े आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया के चलते करीब सात वर्ष तक सब शांत रहता था। हमें अब वैसा समय नहीं मिलेगा क्योंकि मुनीर के पास समय नहीं है। वह कब और क्या करेंगे इस बारे में ठोस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु अगर आप अगले छह सात साल के बारे में सोच रहे हों तो एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और वह यह कि मुनीर यकीनन अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। पाकिस्तान की राजनीति, संस्कृति और इतिहास बताते हैं कि वह अच्छी स्थिति में नहीं होंगे।

हम देखें कि चार सितारा जनरल के रूप में ही वह कितनी ताकत इकट्ठी कर चुके थे। जिस असैन्य सरकार को उनके साथ मिलीभगत करके गठित किया गया था वह पहले ही उनके कदमों में थी। मुनीर के सामने शहबाज शरीफ की देहभाषा और उनके शब्दों पर गौर करिये तो सब स्पष्ट हो जाता है। वह पांचवें सितारे के पहले ही उन्हें 'सिपहसालार' कहकर पुकारने लगे थे। मुनीर हर जरूरी मुद्दे पर बोलते रहे हैं यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान को 370 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात भी कही है।

उन्होंने सेना की शक्ति को चुनौती देने वाले इकलौते नेता इमरान खान को जेल में बंद कर दिया। इसके पहले उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। मुनीर की प्राथमिकता वाला पीएमएल के नेतृत्व में बना गठबंधन इस एकतरफा चुनाव में भी जीत नहीं हासिल कर सका। बहरहाल इसके बावजूद उसे सत्ता सौंप दी गई।

पाकिस्तान में न्यायपालिका ने भी फौजी अदालतों के सामने समर्पण कर दिया है। यहां तक कि नागरिकों के विरुद्ध देशद्रोह जैसे गंभीर मामले चलाने की शक्ति भी उन अदालतों को सौंप दी गई है। संसद उनके हाथों की कठपुतली है जिसे गलत ढंग से हुए चुनाव में चुना गया है। वह संविधान में संशोधनों के लिए रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल की जा रही है। इसके माध्यम से ही उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाया है। न्यायाधीशों को भी सेवा विस्तार और नौकरियों के जरिये लाभान्वित किया जा रहा है। मुनीर ने सबकुछ अपने नियंत्रण में कर लिया है तो अब आगे क्या?

इसे फील्ड मार्शल की नजर से देखिए। अगर वह आगे के सात साल देखते हैं तो शायद म्युचुअल फंड के विज्ञापनों की चेतावनी वाली पंक्ति उन पर भी लागू हो। वह यह कि 'अतीत के प्रदर्शन को भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी न मानें।' पिछला प्रदर्शन तो यही बताएगा कि सत्ता की महत्त्वाकांक्षा रखने वाला हर सेना प्रमुख बुरी गति को प्राप्त हुआ। उन्हें हार झेलनी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े, देश निकाला मिला, चार में से तीन को तो मार दिया गया। यहां अयूब, याह्या, जिया और मुशर्रफ सब एक ही लाइन में नजर आते हैं।

यहां तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी तानाशाह बने तो उनका यही हश्र हुआ। मुनीर के दो पूर्ववर्ती कमर जावेद बाजवा और राहील शरीफ समझदार थे और वर्दी की ताकत के बाद वे खामोशी से पार्श्व में चले गए। हालांकि, मुनीर के पास अभी जो ताकत है उतनी ताकत वाला पाकिस्तानी सेना प्रमुख यह ख्वाब नहीं देखता कि वह सेवानिवृत्त होकर गोल्फ खेलेगा। मुनीर के भीतर मौजूद धार्मिक शिक्षक उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें खुदा ने एक अवसर दिया है। लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें क्या करने के लिए चुना है?

पाकिस्तान में एक ऐसा सेनाध्यक्ष भी रहा है जिसे असैन्य सरकार ने एक साथ रक्षा और गृह मंत्री बनाया था। वह जनरल अयूब थे जो आगे चलकर चीफ मार्शल लॉ प्रशासक बन गए और उसी असैन्य सरकार को हटाकर राष्ट्रपति बन गए। कुछ ही महीनों ने उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हमने याह्या, जिया और मुशर्रफ का हश्र भी देखा है।

इनमें से अंतिम दो ने निर्वाचित सरकारों की भी स्थापना की। राजनीति विज्ञान में पाकिस्तान का यह विशिष्ट योगदान है। वह जनरल सीधे सत्ता में नहीं रहे तो उन्होंने बाहर से सत्ता संभाली। इस खास व्यवस्था को 'हाइब्रिड' सरकार कह सकते हैं। लेकिन मौजूदा व्यवस्था को क्या कहा जाए जहां एक फील्ड मार्शल सरकार को बंधुआ जैसा बनाए हुए है और इकलौता चुनौती देने वाला व्यक्ति जेल में है। तीन दशक से भी पहले जब नवाज शरीफ को सेना ने सत्ता से हटाया था तब उन्होंने एक साक्षात्कार में मुझसे कहा था, 'यह कैसी व्यवस्था है, आधा तीतर, आधा बटेर।' अगली बार जब वह बहुमत में आए तो उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि स्पष्टता आए। या तो सेना का शासन रहे या राजनेता शासन करें। पता नहीं अब जो हो रहा है उसकी वह कैसी व्याख्या करेंगे, जबकि वह खुद राजनीति से निवासित हैं। आप इसे कैसे देखेंगे? यानी एक सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बनाया जाना, सबसे प्रमुख नेता का दो साल से जेल में बंद होना और हास्यास्पद ढंग से चुनी गई असैन्य सरकार का होना।

क्या आपको कक्षा पांच की जीव विज्ञान की पुस्तक का वह पाठ याद है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई जीव डकबिल्ड प्लैटिपस के बारे में बताया गया था जो एक स्तनपायी, चिड़िया और सरीसृप तीनों के गुण रखता है। यह पाठ विभिन्न प्रजातियों के उद्भव के बारे में बताता है। मुझे पता है आप हंस रहे होंगे लेकिन कृपया मत हंसिए। फील्ड मार्शल मुनीर इस समय इसी तरह का राज कर रहे हैं। पांचवां सितारा जीत के झूठे दावे की तरह बोझ बन गया है। भारत के लिए बेहतर होगा कि वह तैयार रहे। मुनीर के पास 5-7 साल का समय नहीं है। वह जल्दी ही आक्रामक हो सकते हैं। शायद अगले एक साल में ही वह ऐसा करें।

भारतीय युवा कैसे व्यतीत करते हैं अपना समय?

अमिताभ साहा और गोपाल साहा

समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) यह समझने में काफी सहायक होता है कि विभिन्न उम्र दायरे में आने वाले लोग (महिला एवं पुरुष) सवैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों में किस तरह शिरकत करते हैं। टीयूएस आंकड़े दर्शाते कि किस प्रकार स्त्री-पुरुष मानदंड और सामाजिक भूमिकाएं पुरुषों और महिलाओं के समय के विभाजन को प्रभावित करती हैं, चाहे वह घर के भीतर हो या व्यापक समाज में। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्यों पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों पर स्त्री-पुरुष, उम्र और स्थान के आधार पर व्यतीत समय की गणना के लिए टिकाऊ विकास, 2030 की अपनी कार्य योजना (एजेंडा) में एक संकेतक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नारी-पुरुष समानता एवं महिला सशक्तीकरण की प्रगति पर नजर रखना है।

समय उपयोग पर भारत में सर्वेक्षण: भारत में वर्ष 2019 और 2024 में समय उपयोग पर दो सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में प्रत्येक परिवार में 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की 24 घंटे (साक्षात्कार के एक दिन पहले 4 बजे सुबह से लेकर साक्षात्कार के दिन 4 बजे सुबह तक) की बीच की गतिविधियां दर्ज की गईं। प्रत्येक सर्वेक्षण में लगभग 4.5 लाख लोगों की प्रत्येक दिन नौ बड़ी गतिविधियों का अध्ययन किया गया। इस नमूने में लगभग 60 फीसदी लोग ग्रामीण और 40 फीसदी शहरी क्षेत्रों के थे।

भारतीय युवा के समय के उपयोग का प्रारूप: राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार भारत में 15-29 वर्ष के 'युवाओं' की एक बड़ी आबादी है। जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह ने उनकी आबादी वर्ष 2024 में 37 करोड़ (1.41 अरब लोगों में) रहने का अनुमान लगाया था। उनकी इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उनके समय के उपयोग का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

वर्ष 2019 में प्रति दिन 1,440 मिनट में से भारतीय युवाओं ने रोजगार-संबंधित गतिविधियों पर 148 मिनट खर्च किए। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 158 मिनट हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर की संख्या वित्त वर्ष 2019 के 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1.31 करोड़ हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि इन शुद्ध पेरोल वृद्धि में 29 वर्ष से कम उम्र के लोगों की संख्या लगभग 61 फीसदी थी। इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में काफी कम हो गई।

वर्ष 2019 में काम के अलावा भारतीय युवाओं ने सीखने और लोगों से घुलने-मिलने, दोनों में से प्रत्येक पर 125 मिनट बिताए। 136 मिनट उन्होंने खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च किए जबकि 171 मिनट घरेलू एवं देखभाल के कार्यों पर बिताए। शेष बचे 735 मिनट उन्होंने अपनी देखभाल एवं अन्य गतिविधियों पर खर्च किए। वर्ष 2024 तक खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आवंटित समय बढ़कर 156 मिनट हो गया जबकि सीखने (124 मिनट), बिना भुगतान वाले घरेलू एवं देखभाल कार्यों (177 मिनट) पर व्यतीत समय में तुलनात्मक रूप से कोई बदलाव नहीं दिखा। खुद की देखभाल पर व्यतीत समय भी 2024 में काफी कम हो गया।

समय उपयोग में ग्रामीण-शहरी अंतर: तेज शहरीकरण, व्यापक विकास और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के उभरते अवसरों के कारण वर्ष 2024 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं के बीच समय के उपयोग में समानता बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्र के युवा अब अपनी देखभाल गतिविधियों के बाद अधिकतर समय रोजगार संबंधित कार्यों पर बिता रहे हैं। 2019 में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने ज्यादातर समय घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक कार्यों पर (स्व: देखभाल छोड़कर) बिताए जबकि शहरी क्षेत्र के युवाओं ने अपने समय मुख्य रूप से रोजगार संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए। वर्ष 2024 तक रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर व्यतीत समय ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ गया।

वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक ग्रामीण युवाओं के मामले में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 37.8 फीसदी से बढ़कर 48.1 फीसदी हो गई जबकि कामगार आबादी अनुपात 31.7 फीसदी से बढ़कर 44 फीसदी हो गया। वैतनिक या भुगतान वाले कार्यों में हाल में बढ़ोतरी संकेत देती है कि सरकार द्वारा व्यापक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा श्रम बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं।

समय उपयोग में नारी-पुरुष असमानता: युवा पुरुष एवं महिलाएं वैतनिक और अवैतनिक सेवाओं पर अपने समय का आवंटन जिस रूप में करते हैं उसमें बड़ी असमानता दिखी है। 'परिवार के सदस्यों के लिए एक दिन में प्रति व्यक्ति अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल सेवाओं पर व्यतीत औसत समय' के अनुमान बताते हैं कि 2019 में युवा पुरुष और महिलाओं के मामले में यह क्रमश: 2.22 फीसदी और 21.60 फीसदी रहा और 2024 में क्रमश: 2.36 फीसदी और 22.01 फीसदी दर्ज किया गया। इस तरह, अवैतनिक कार्य योगदान में नारी-पुरुष असमानता में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई। स्त्री-पुरुष समानता की तरफ कदम: पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में भारी इजाफा हुआ है। वर्ष 2018-19 और 2023-24 के बीच ग्रामीण महिलाओं के लिए एलएफपीआर लगभग दोगुना हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में यह 15.8 फीसदी से बढ़कर 30.8 फीसदी हो गई जबकि शहरी क्षेत्र में 17.1 फीसदी से बढ़कर 23.8 फीसदी हो गई। श्रम बल में और अधिक युवा महिलाओं के शामिल होने से रोजगार संबंधित गतिविधियों पर व्यतीत औसत समय भी बढ़ गया है।

'विकसित भारत' के लक्ष्य (जिसमें अर्थव्यवस्था में पुरुष और महिलाओं के बराबर योगदान की कल्पना की गई है) के अनुरूप ये रुझान काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। महिलाओं की वैतनिक गतिविधियों में हिस्सेदारी बढ़ने और इसके अलावा उन पर अवैतनिक घरेलू जिम्मेदारियों का भी बोझ होने से पुरुषों की तुलना में उनके पास मनोरंजन, घूमने और स्वयं पर ध्यान के लिए कम समय बचता है। यह चिंता का विषय है। पुरुषों में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं के साथ साझा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना परंपरागत स्त्री-पुरुष मान्यताओं से उबरने और स्त्री-पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

(लेखक क्रमश: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में उप-महानिदेशक और उप-निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

मौसम का नया साथी 'जीएफएस'

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस मॉनसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जारी किया है, जो देश के लिए एक सुखद खबर है। इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का शुभारंभ हुआ है, जो वैश्विक मौसम विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका नया ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम (जीएफएस) मौजूदा प्रणाली से कहीं अधिक उन्नत है और मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए वरदान साबित होगा। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जो बड़े संकट का संकेत देती है। ऐसे में जीएफएस की जिला और पंचायत स्तर तक की सटीक भविष्यवाणी बेहद महत्त्वपूर्ण है। यह प्रणाली भारी बारिश, तूफान और अन्य चरम घटनाओं के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन की तैयारी में मदद करेगी। यह पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है, जिसे सुपरकंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता ने और भी मजबूत बनाया है, जिससे पूर्वानुमान कुछ ही घंटों में अत्यधिक सटीकता के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसानों को मौसम की सटीक जानकारी समय पर मिलने से बोआई, सिंचाई और कटाई की योजना बेहतर हो सकेगी। वहीं, मछुआरों को समुद्री हलचल की चेतावनी से उनके जान-माल की रक्षा होगी। इस प्रणाली का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता और बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। स्थानीय और सरल भाषा में पूर्वानुमानों को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना होगा। पंचायतों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से मौसम संबंधी प्रशिक्षण और कार्यशालाएं भी आयोजित करनी होंगी।

राजूराम प्रजापत, नागौर

अगरतला में भारी बारिश के बाद हुए जलजमाव में फंसे लोगों को रविवार को बचाव दल ने निकाला

मॉनसूनी बारिश से आई आफत

देश में 12 दिन पहले मॉनसून की दस्तक के बाद पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में भारी बारिश आफत बन कर आई है। पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की खबरें हैं। इस साल मॉनसून जल्द आने से बारिश भी खूब हो रही है। सरकार की मॉनसून को लेकर तैयारी शायद ही पूरी हुई हो लेकिन मॉनसून ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मणिपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी दिल्ली में कुछ वर्ष पहले भारी बारिश के बाद यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी। इसकी वजह से लाल किला परिसर, राजघाट तथा आईटीओ में बाढ़ का पानी घुस गया था। सरकार को इस साल बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। अगर मॉनसून पहले आया है तो ऐसी संभावना है कि बारिश भी जम कर होगा। अतः बाढ़ प्रभावित चिह्नित क्षेत्रों के अलावा अन्य जगहों पर भी पुख्ता तैयारी हो ताकि बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब नहीं बन सके।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

इजरायल ने रविवार को गाजा में हवाई हमले किए। इजरायली गोलीबारी से गाजा पट्टी में खाद्य सामग्री लेने के लिए सहायता केंद्र जाते समय कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए।